● वर्ष-3
● अंक-156
रायपुर, गुरुवार
08 फरवरी 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› यूपीएससी क्रैक करने के ...

पीएससी के पूर्व अध्यक्ष सोनवानी पर अपराध दर्ज

परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की होगी जांच

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। इस प्रकरण की जांच केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के परिपालन में आर्थिक अपराध अन्वेषण द्वारा लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके परिपालन में गृह (पुलिस) विभाग द्वारा महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर को अवगत कराया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा वर्ष 2021 जो 170 पदों के लिए ली गई थी और जिसके परिणाम 11 मई 2021 को जारी किए जाने के पश्चात् राज्य लोकसेवा आयोग पर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए श्री ननकीराम कंवर व अन्य के माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी।

शिकायती पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष श्री टामन सिंह सोनवानी, तत्कालीन सचिव श्री जीवन किशोर ध्रुव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक एवं शासन तथा आयोग में तत्समय पदस्थ संलिप्त लोकसेवकगण और संबंधित राजनेतागण एवं अन्य के द्वारा अपने-अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तथा राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की चयन प्रक्रिया वर्ष 2020 एवं 2021 तथा असिस्टेंट प्रोफेसर चयन परीक्षा में नियम विरूद्ध तरीके से आपराधिक षड़यंत्र करते हुये अपने पुत्र, पुत्री व रिश्तेदारों को कई पात्र योग्य अभ्यार्थियों के बदले इनका चयन शासकीय पदों पर करते हुए शासन एवं उन योग्य अभ्यार्थियों के साथ भ्रष्ट आचरण करते हुये छल कारित किया गया है, जो कि धारा 120 बी, 420, भादवि एवं धारा 7, 7 (क), एवं 12 भ्र.नि.अ. 1998 यथा संशो. 2018 के तहत अपराध कारित किया जाना पाया गया है, अतः अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

ईओडब्ल्यू में सीजीपीएससी की एफआईआर पर मुख्यमंत्री ने किया ट्वीट, कहा-

बच्चों के साथ हुए अन्याय का होगा हिसाब

ईओडब्ल्यू में सीजीपीएससी की एफआईआर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर लिखा, आज सीजीपीएससी महाघोटाले के आरोपी पूर्व अधिकारियो एवं नेताओं पर ईओडब्ल्यू ने एफ़आईआर दर्ज कर दी है. इस महाघोटाले में अपने भविष्य की बलि देने वाले मेरे सभी बच्चो को आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ हुए अन्याय का हिसाब होगा.

साय ने आगे लिखा, गुनहगार बचेंगे नहीं, हम आपकी प्रतिभा का सौदा करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे. बता दें कि छत्तीसगढ़ में पीएससी भर्ती गड़बड़ी मामले में तत्कालीन पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव समेत कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. भाजपा लगातार इस मामले को उठाता रहा है. सरकार में आने से पहले भाजपा ने वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो पीएससी मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा. भाजपा ने इस मामले को अपने आरोप पत्र में भी शामिल किया था. ऐसे में वादे के मुताबिक, भाजपा सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला भी ले चुकी है. अब दोषियों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है. गौरतलब है कि 11 मई 2023 को सीजी पीएससी 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था. इसमें 171 पदों पर पीएससी ने भर्ती की थी, जिसमें 15 लोगों का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ था. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मेरिट लिस्ट में पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों को जगह मिली है. इन आरोपों के बाद लोक सेवा आयोग आरोपों के घेरे में थी और बीजेपी के नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. इसके बाद कोर्ट ने 18 लोगों की नियुक्ति को रोकने के आदेश दिए थे.

छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन से संबंधित परमिट तथा अन्य स्वीकृति होंगी ऑनलाईनः मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन से संबंधित एवं अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाईन की जाएगी। उन्होंने कहा कि खनिज प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था तथा सुशासन की दृष्टि से इन प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में खनिज विभाग के संचालक द्वारा 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर यह व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई-परमिट का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इस आदेश के माध्यम से इसके पहले जो ऑनलाईन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था। जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे और परिवहन में भी विलंब होता था।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि खनिज विभाग में पूर्व में लागू ऑनलाईन व्यवस्था के तहत कोयले के परिवहन हेतु खनिज

मुख्यमंत्री ने विस में की घोषणा

ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पट्टेदार द्वारा स्वतः अपने कार्यालय से खनिज परिवहन हेतु ई-परमिट एवं ई-ट्रांजिट पास प्राप्त कर बिना खनिज कार्यालय आये अपना परिवहन किया जा रहा था। पिछली सरकार में नवीन ऑफलाईन प्रकिया के लागू होने से ई-टीपी लागू करने में विलंब हुआ और कई कोयला खदानों में निकासी अवरूद्ध होने से रायल्टी राजस्व की हानि हुई, जिस पर भारत सरकार ने भी दो बार राज्य सरकार को पत्र जारी कर आपत्ति ली गई थी। इसके अतिरिक्त मानवीय हस्तक्षेप शुरू होने से अवैध उगाही एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला एवं प्रदेश की छवि धूमिल हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न संस्थानों ने ऑफलाईन व्यवस्था के संबंध में आदेश को निरस्त करने की लगातार मांग की एवं अवैध लेनदेन एवं उगाही का आरोप भी लगाया है। इसी अनुकम में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच उपरांत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है।

साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में निदेशालय ने एंटी करप्शन, ब्यूरो में प्रकरण दर्ज किया गया है, जो विवेचनाधीन है। उन्होंने कोल परिवहन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था एवं सुशासन को ध्यान में रखकर खनिज विभाग द्वारा 15 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र एवं इसके अनुक्रम में जारी अन्य सभी अनुषंगी निर्देशों को निरस्त करने की घोषणा की।

श्वेत पत्र पेश कर सकती है सरकार, बजट पर चर्चा रास में संभव

कांग्रेस का ब्लैक पेपर लाने का ऐलान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार संसद में अर्थव्यवस्था को लेकर श्वेत पत्र पेश कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करने के दौरान ही यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति में आए बदलावों पर श्वेत पत्र पेश करने की घोषणा की थी। बजट सत्र में राज्यसभा में अंतरिम बजट और जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर चर्चा होने की संभावना भी है। बता दें कि बुधवार को लोकसभा में इसकी चर्चा की गई थी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय सलाहकार समिति के चुनाव से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश कर सकती है। वहीं राज्यसभा में ही आज श्वेत पत्र भी पेश किया जा सकता है, जो कि एक अनौपचारिक रिपोर्ट होती है। इसमें किसी विषय पर जानकारी या सर्वेक्षण के परिणाम का सारांश होता है। इसमें किसी विषय के बारे में जानकारी होती है जो काम करने के बेहतर तरीकों पर सुझाव देता है।

बता दें कि सरकार श्वेत पत्र इसलिए ला रही है ताकि ये पेश किया जा सके कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान देश में अर्थव्यवस्था संकट में थी। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को संकट से निकाल कर बाहर लाई है। अब सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है।

पारित हुआ अंतरिम बजट- गौरतलब है कि इससे पहले लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी और इस तरह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट को पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। सदन ने विधेयक पर चर्चा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब के बाद 'वित्त विधेयक, 2024' को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। चौधरी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आयकर की दरों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है।

कांग्रेस लाएगी ब्लैक पेपर- न्यूज़ एजेंसी एएनआई के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन करके संसद में ब्लैक पेपर पेश करने वाले हैं। ये ब्लैक पेपर कांग्रेस केंद्र सरकार के बीते 10 वर्षों के जवाब में लेकर आएगी।

लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी दी, अंतरिम बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी हुई

नई दिल्ली। लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी और इस तरह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट को पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। सदन ने विधेयक पर चर्चा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब के बाद 'वित्त विधेयक, 2024' को ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान कर दी। चौधरी ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आयकर की दरों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग एक करोड़ प्रत्यक्ष करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2009-10 की 25,000 रुपये और 2010-11 से 2014-15 तक की 10,000 रुपये की मांग को वापस लिया जाएगा।

चौधरी ने कहा कि चुनावी वर्ष होने के बावजूद सरकार ने उपयुक्त प्रावधानों के अतिरिक्त और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए अंतरिम बजट के माध्यम से देश के विकास को प्राथमिकता दी है और 2047 तक 'विकसित भारत' बनाने की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है। इससे पहले लोकसभा ने आज 2024-25 के लिए 47.66 लाख करोड़ रुपये के अंतरिम बजट को और अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद ध्वनिमत से मंजूरी दी थी। सदन ने संबंधित विनियोग विधेयक को भी पारित किया जिसमें सरकार को अगले वित्त वर्ष के पहले चार महीने के लिए खर्च करने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 1.8 लाख करोड़ रुपये के बजट को भी मंजूरी दी।

प्रमुख समाचार

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की अहम भूमिका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट' (टेरी) द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के लिए एक लिखित संदेश में मोदी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा पर देश का ध्यान भविष्य के लिए जिम्मेदारी की गहरी भावना को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, ''हमारा देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। हमारी जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भी 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की भावना कई मुद्दों पर हुई चर्चाओं में प्रदर्शित हुई थी।'' उन्होंने कहा कि व्यक्तियों को बदलाव का प्रेरणास्त्रोत बनने के लिए प्रेरित करने वाली 'मिशन लाइफ' जैसी पहल और 'पंचामृत' लक्ष्यों के बारे में भारत की व्यापक दृष्टि एक स्वच्छ, हरित और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए देश की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जलवायु न्याय को मार्गदर्शक होना चाहिए

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में जलवायु न्याय की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के असंगत प्रभाव को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों में जलवायु न्याय की अहम भूमिका होनी चाहिए। स्वतंत्र 'थिंक टैंक' टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए धनखड़ ने वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और जलवायु न्याय पहल में भारत की अग्रणी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''वैश्विक नेतृत्व को सभी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और जलवायु न्याय को मुख्यधारा में लाना चाहिए, इन सिद्धांतों को हमारे समाज के ढांचे में शामिल करना चाहिए।'' धनखड़ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन असमान रूप से सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करता है ''इसलिए, जलवायु न्याय को इसका मार्गदर्शक बनने की जरूरत है।'' उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सतत विकास और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है.

मुठभेड़ के दौरान 8 लाख के इनामी नक्सली को किया ढेर

दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षाबल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 लाख रुपये के इनामी नक्सली को मार गिराया है. पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि जिले के गोंदपल्ली,परलागट्टा और बड़ेपल्ली के बीच पहाड़ी जंगल में सुरक्षाबलों ने नक्सली चन्द्रन्ना उर्फ सत्यम को को मार गिराया. वहीं नारायणपुर में पुलिस की टीम ने अबूझमाड़ के बेड़मामेटा के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, इन नक्सलियों के पास से नक्सल सामग्री बरामद हुई है. जानकारी के मुताबिक, नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में डीआरजी, बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ 231 के यंग प्लाटून का संयुक्त बल नक्सल गस्त सर्च अभियान पर रवाना हुए थे. इसी दौरान उन्हें नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. तभी गोंदपल्ली, परलागट्टा और बड़ेपल्ली के बीच पहाड़ी जंगल में सर्च पर निकले जवानों का सामना नक्सलियों से हो गया. मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबल के जवानों ने चन्द्रन्ना उर्फ सत्यम को मार गिराया. जिसका शव बरामद कर लिया गया है. जानकारी के मुताबिक सत्यम साल 2013 के पूर्व माड़ डिविजन का डीवीसी मेम्बर था.

झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटीः खड़गे

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। मोदी ने आज राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान खड़गे पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा था। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि एनडीए का मतलब नो डेटा अवेलेबल है। उनके(भाजपा) पास कोई आंकड़े नहीं हैं। वे सच नहीं बोल सकते, वे झूठ बोलते रहते हैं। खड़गे ने कहा कि संविधान को नहीं माननेवाले, जिन्होंने दंडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए वो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी ने यूपीए सरकार पर अनगिनत झूठी बातें कहीं। इसके साथ ही खड़गे ने मोदी से कई सवाल भी पूछे हैं। खड़गे ने पूछा कि यूपीए के दौरान बेरोज़गारी दर 2.2% था, आपके दौरान 45 सालों में सबसे ज़्यादा क्यों है? यूपीए के 10 सालों में दौरान जीडीपी विकास दर औसतम 8.13त्न रहा, आपके दौरान केवल 5.6% क्यों? उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक की माने तो 2011 में ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।

पीएससी घोटालाः सरकार इस मामले को लेकर संजीदाः चौधरी

रायपुर. छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती में हुई गड़बड़ी के मामले में ईओडब्ल्यू ने तत्कालीन चेयरमैन टामन सोनवानी, जीवनलाल ध्रुव समेत कई नेताओं के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कर लिया है. सूबे में भाजपा सरकार आने के पहले पीएससी मामले की लड़ाई की अगुवाई करने वाले अहम चेहरों में से एक ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद संजीदा है. इस गड़बड़ी में जो भी ज़िम्मेदार होगा उसके खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. यह मामला हमारे लिए राजनीति से ज़्यादा युवाओं को न्याय दिलाने का है. हम पीएससी भर्ती में रिफॉर्म लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों उनके माता पिता जो अपने बच्चों को गहना बेचकर, खेत बेचकर पढ़ाई के लिए भेजते थे. उनके साथ अन्याय हो रहा था. हम उनकी लड़ाई चार साल से लड़ रहे थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से कहा था कि पीएससी में जो गड़बड़ी हुई है. उसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार अब उस रास्ते आगे बढ़ रही है. सरकार ने सीबीआई जांच का भी निर्णय लिया है. इस मामले की सुक्ष्मता के साथ जांच की जएगी.

यूसीसीः सही दिशा में छोटा कदम, पूरे देश के लिए साबित हो सकता है नजीर

विराग गुप्ता

संविधान के प्रावधानों को साकार करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर कानून बनाने की ऐतिहासिक पहल की है। संविधान की शुरुआत %सत्यमेव जयते% से होती है, जहां सारनाथ का सिंह कानून के शासन के महत्व को दर्शाता है। गणतंत्र के 75 साल बाद भी यूसीसी पर चल रहे असमंजस को संविधान में उकेरे गए पौराणिक आख्यानों से समझा जा सकता है। संविधान सभा में के. एम. मुंशी जैसे सदस्यों की बात मानकर अगर यूसीसी को मूल अधिकार वाले अध्याय में शामिल किया जाता, तो यह कानून सभी के लिए बाध्यकारी हो जाता। मूल अधिकार वाले अध्याय-3 में रावण को पराजित करने के बाद लौट रहे राम-लक्ष्मण और सीता के साथ अधर्म पर धर्म की जीत का चित्र है। लेकिन नजीरुद्दीन अहमद जैसे सदस्यों के विरोध की वजह से इसे मार्गदर्शक सिद्धांत वाले अध्याय-4 में डाला गया। जहां कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण गीता के उपदेश से अर्जुन के मोह को हरने की कोशिश करके कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

संविधान में स्त्री और पुरुष, दोनों को बराबरी से चुनावों में वोट डालने का अधिकार है। सभी धर्मों के स्त्री और पुरुषों के लिए आपराधिक कानून भी समान हैं। लेकिन शादी, तलाक, बच्चे और संपत्ति से जुड़े सिविल मामलों में धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव होना दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद की बातों पर अमल करते हुए वर्ष 1956 में हिंदू कोड बिल के साथ मुस्लिम समुदाय के लिए भी कानून बनना चाहिए था। वर्ष 1985 में शाहबानो मामले के बाद भी इस बारे में ठोस कदम उठाया जा सकता था। उसके बजाय तुष्टीकरण नीति के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने से कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा ही मिला।

इंडोनेशिया, बहरीन, तुर्किये और लेबनान जैसे कई मुस्लिम देशों में आधुनिक कानून लागू हैं, तो फिर भारत में ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेताओं द्वारा धर्म के आधार पर यूसीसी के विरोध को प्रधानता क्यों मिलनी चाहिए? पर्सनल लॉ के नाम पर रजस्वला होने के बाद नाबालिग मुस्लिम लड़कियों की शादी का समर्थन करने वालों को शरीयत ऐक्ट की धारा 3-बी पढ़ने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट ऐक्ट की धारा-11 के तहत ऐसे अनुबंध में दोनों पक्षों का सक्षम यानी बालिग होना जरूरी है। इसलिए शरीयत ऐक्ट की आड़ में नाबालिग मुस्लिम बच्चों की शादी गलत है। सियासी बवाल और धार्मिक विरोधाभास के साथ कई कानूनी चुनौतियां भी हैं। पहला, लिव-इन के दौर में बहु-विवाह पर प्रभावी रोक कैसे लगेगी? प्रस्तावित कानून में लिव-इन में रहने की स्वघोषणा के साथ अभिभावकों को सूचना देने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानून के बावजूद सभी शादियों के रजिस्ट्रेशन के नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो फिर लिव-इन के दौर में शादी और तलाक के मामलों का निर्धारण कैसे होगा?

दूसरा, देश के कानून के अनुसार, शादी के लिए न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने पर संसद में कई साल से सिर्फ मंथन हो रहा है। उत्तराखंड में पूर्व जज की कमेटी ने भी माना है कि बाल-विवाह के पीछे अशिक्षा और गरीबी बड़ी वजह है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, नाबालिग बच्चों के सहमति से बने संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। इसलिए लड़कियों की उम्र को बढ़ाने के बजाय लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र को भी 18 साल करने पर विचार होना चाहिए। इससे लैंगिक समानता के साथ कानून-पालन का भाव बढ़ेगा। तीसरा, कुछ लोग यूसीसी को जनसंख्या विस्फोट से निपटने का कारगर उपाय मानते हैं। भारत में कई दशकों से जनसंख्या नियंत्रण पर सिर्फ कानून बनाने की बात हो रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि अगले 10 वर्षों में कामकाजी आबादी कम होने के साथ बूढ़ों की तादाद भी बढ़ जाएगी। यूसीसी के तहत लिव-इन से पैदा होने वाले नाजायज बच्चों को भी कानूनी अधिकार मिलेंगे। सरोगेसी के तहत भी लोग बच्चे पैदा करते हैं। इन नई चुनौतियों के बीच दो बच्चों की नीति पर प्रभावी अमल कैसे होगा?

उत्तराखंड के अलावा, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी ऐसी पहल हो रही है। समवर्ती सूची में यूसीसी से जुड़े अनेक मामलों पर संसद ने कानून बनाए हैं। कई विषयों पर कानून बनने की जोरों से बात हो रही है। इसलिए उत्तराखंड विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकते हैं। सियासत के नजरिये से राज्यों में कानून बनाना लाभकारी हो सकता है, लेकिन कई राज्यों में मनमाने तरीके से कानून निर्माण से गलत मिसाल के साथ सांविधानिक अराजकता भी बढ़ सकती है।

कवर्धा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, भागे माओवादी

कवर्धा। काफी लंबे समय बाद कवर्धा में पुलिस और नक्सलियों का आमना सामना हुआ है। घटना चिल्फी थाना अंतर्गत माराडबरा जंगल की है। मंगलवार शाम को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बोड़ला एरिया कमेटी के 7 हथियारबंद वर्दीधारी नक्सलियों को माराडबरा के जंगल की ओर जाते देखा गया है। इस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम नक्सलियों का पता लगाने जंगल गई। वहां पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। लगभग 20 मिनट तक पुलिस ने 49 राउंड फायरिंग की।

जवानों के हथियार लूटने की थी प्लानिंग- पुलिस की फायरिंग के बाद कमजोर पड़ते नक्सली पहाड़ी की आड़ लेकर भागने में कामयाब हो गए। फायरिंग बंद होने के बाद पुलिस ने जंगल में सर्चिंग शुरू की तो भारी मात्रा में नक्सलियों का दैनिक उपयोगी सामान बरामद हुआ। जब्त सामग्री को चिल्फी थाना में रखा गया है। घटना के बाद पुलिस ने जंगल में सर्चिंग बढ़ा दी है। एसपी अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि की।

कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव ने कहा समर, नवीन और जरीना समेत 7 वर्दीधारी नक्सली माराडबरा जंगल में देखने की सूचना के बाद पुलिस की एक टीम रवाना हुई, लेकिन नक्सलियों ने हथियार लूटने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने नक्सलियों को सरेंडर करने बोला लेकिन नक्सली लगातार फायरिंग कर रहे थे, तब पुलिस ने आत्मसुरक्षा में जवाबी फायरिंग किया।

छत्तीसगढ़ डीजीपी अशोक जुनेजा ने कुछ दिन पहले ही कवर्धा में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस की ज्वाइंट मीटिंग की थी। इस मीटिंग में नक्सल गतिविधियों

के खिलाफ कारवाई करने पर अहम चर्चा हुई थी। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सर्जरी करने की बात कही गई थी। इस बैठक के कुछ दिन बाद ही नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है।

नक्सलियों का प्रचार-प्रसार करने वाले छह लोग गिरफ्तार, पोस्टर और बैनर बरामद

कांकेर। नक्सलियों के प्रचार-प्रसार के लिए बैनर, पोस्टर बांटने आए छह लोगों को कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंतागढ़ थाना क्षेत्र के नवागांव में पुलिस ने चेक पोस्ट के पास नक्सलियों का प्रचार-प्रसार कर रहे सदस्य को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नक्सली बैनर, पोस्टर बरामद किया गया है। वहीं, तीन मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है।

कांकेर पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ेधौसा के जंगल से अंतागढ़ शहर की ओर नक्सलियों का बैनर-पोस्टर लगाने और नक्सली संगठन का प्रचार-प्रसार करने के लिए नक्सल सदस्य आने वाले हैं। सूचना पर थाना प्रभारी अंतागढ़ के नेतृत्व में पुलिस टीम रवाना हुई थी। नवागांव नदी पुलिया के पास सड़क पर पुलिस ने मोबाइल चेक पोस्ट लगाया था। इस दौरान आमागांव तरफ से अंतागढ़ आ रहे तीन बाइक पर कुल छह नक्सल प्रचार-प्रसार सदस्यों को घेराबंदी कर पकड़ा गया।

पूछताछ करने पर अपना नाम लखन लाल नुरूटी, शैलेंद्र कुपाल, सुकरेन ध्रुव, हेमराज मंडावी, हरिश कुमार बघेल, सुनतेर गावड़े ग्राम बड़ेधौसा के नक्सल प्रचार-प्रसार सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि प्रचार-प्रसार सदस्य के रूप में काम करना कबूल किया तथा अपने साथ रखे माओवादियों के तीन लाल कलर के बैनर, 50 पंपलेट को अंतागढ़ शराब भट्ठी के पास लगाने वाले थे।

नक्सलियों ने ग्रामीण युवक को उतारा मौत के घाट, इलाके में दहशत का माहौल

बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तिम्मापुर में नक्सलियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। मृतक ग्रामीण की नक्सलियो ने धारदार हथियार से वार हत्या कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तिम्मापुर में नक्सलियों ने मिच्चा हड़मा (25) की धारदार हथियार व टंगिया से सिर और गर्दन में वार हत्या कर दी है। ग्रामीण हड़मा का शव तिम्मापुर स्कूल के पास सड़क पर मिला हैं। मामले की तस्दीक के बाद पुलिस ग्रामीण हड़मा के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही हैं। ग्रामीण की हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है।

दुर्ग जंक्शन में जनप्रतिनिधियों ने दिखाई हरी झंडी

अयोध्या राम लला दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना

दुर्ग। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई है। इस ट्रेन को आस्था स्पेशल नाम दिया गया है।इस ट्रेन में जाने वाले श्रद्धालुओं के आने जाने, भोजन और अयोध्या में रुकने का प्रबंध सरकार ने किया है। इस ट्रेन की खास बात ये है कि इसमें पंजीयन के बाद 1344 लोगों को अयोध्या भेजा गया। दुर्ग जंक्शन से 1340 श्रद्धालुओं को लेकर ये ट्रेन रवाना हुई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन चलवाई है।जिसमें दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन को दुर्ग जंक्शन से रवाना किया गया।इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह ,अयोध्या यात्रा के प्रदेश प्रभारी धरम लाल कौशिक, मंत्री दयालदास बघेल,स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल विशेष रूप से दुर्ग रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे।जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया।

इस योजना के तहत दर्शनार्थियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है।इसके लिए पहले हर विधानसभा में पंजीयन करवाया गया है। सभी लोगों की टिकट कन्फर्म होने के बाद उन्हें आईकार्ड भी दिया गया है।दुर्ग संभाग के 8 जिलों

से लगभग 1340 दर्शनार्थियों का जत्था रवाना हुआ। अयोध्या यात्रा के प्रदेश प्रभारी धरमलाल कौशिक ने हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि घोषणा के मुताबिक प्रदेश के लोगों को अयोध्या दर्शन कराया जा रहा है।इस वजह से पूरा छत्तीसगढ़ राममय नजर आ रहा है।

इस दौरान अयोध्या दर्शन के लिए जाने वाले दर्शनार्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अयोध्या में भव्य राममंदिर के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं का कहना है कि इसके लिए सनातियों ने लंबा संघर्ष किया। लेकिन अब सुखद क्षण आया है।इस ट्रेन में 20 बोगी लगाया गई है।जिसमें एक विधानसभा सीट के 72 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। हर एक बोगी में दो-दो आरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। 9 फरवरी को दुर्ग ये ट्रेन वापस लौटेगी।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के गढ़ में अस्पताल बीमार

कोरिया। स्वास्थ्य सुविधा के मामले में कोरिया कॉलरी में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। पांच हजार की आबादी वाले क्षेत्र में अस्पताल नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात गांव से भी बदतर हैं। कोयला खदान बंद होने के कुछ समय बाद ही एसईसीएल का अस्पताल वीरान हो गया। एसईसीएल अस्पताल भवन खंडहर हो चुका है। यही कारण है कि लोगों को इलाज के लिए 16 किमी दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है, जो आपातकाल स्थिति में जान की बाजी लगाने के बराबर है।

दरअसल, ये क्षेत्र प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा मनेंद्रगढ़ में पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्लम एरिया के लिए शुरू की गई मेडिकल मोबाइल यूनिट बस सेवा कभी कभार वार्डों में भेजी जाती है। लेकिन ये काफी नहीं है। कोरिया वासियों की मांग है कि पुराने अस्पताल में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाकर इसे खोला जाए। इस बारे में कोरिया वासियों का कहना है कि, इतनी बड़ी आबादी को लेकर चिकित्सा सुविधा का अभाव होना ठीक नहीं है। यहां अस्पताल बनाकर डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था होनी चाहिए थी। न तो चिरमिरी नगर निगम और न ही एसईसीएल प्रबंधन की ओर से इस समस्या को गंभीरता से

लिया जा रहा है। लोग चुने गए जनप्रतिनिधि से इस दिशा में सकारात्मक प्रयास की उम्मीद कर रहे हैं।

ग्रामीण ने कहा कोराना काल में अस्पताल में कुछ समय एक डॉक्टर सेवा दे रहे थे, लेकिन कोविड के बाद यह सुविधा भी खत्म कर ली गई। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर राज्य सरकार ने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कराया लेकिन भवन बनने के बाद से इसमें ताला लगा हुआ है। करीब आठ साल से भवन में स्टाफ और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने से लोग 6 किलोमीटर दूर डोमनहिल स्वास्थ्य केंद्र या फिर 16 किमी दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने को मजबूर हैं।

ऐसे में साफ है कि लोगों की परेशानी से सरकार को कोई मतलब नहीं है। कुछ साल पहले स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में एक डॉक्टर को नियुक्त किया था। लेकिन कुछ माह बाद यह व्यवस्था भी बंद हो गई। प्रशासन की ओर से भवन की पुताई करवाई गई है लेकिन यहां स्वास्थ्य व्यवस्था कब उपलब्ध कराई जाएगी ये किसी को नहीं पता।

आलम यह है कि 75 हजार से अधिक आबादी वाले नगर निगम चिरमिरी में स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर बड़ा बाजार में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डोमनहिल, पोड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। एसईसीएल ने कॉलरी क्षेत्रों के डिस्पेंसरी और छोटे अस्पतालों को बंद कर दिया है। क्षेत्र में भी पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। यही कारण है कि लोग इलाज के लिए बिलासपुर, रायपुर जाने को मजबूर हैं।

जल प्रदाय योजना के लिए रोड़ा बनी डायाफ्राम वॉल

स्कीम की सफलता के लिए चिंतित पीएचई विभाग, इधर एनआईटी की रिपोर्ट ने उड़ा दी नींद

गरियाबंद। किडनी रोग से ग्रसित सुपेबेड़ा समेत 9 गांव के लोगों को तेल नदी से पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनी 8।45 करोड़ की सामूहिक जल प्रदाय योजना का निर्माण शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले ही उसकी सफलता में सिंचाई विभाग द्वारा बनाया जा रहा डायफ्राम वॉल रोड़ा साबित हो रहा है।

2 करोड़ की लागत से बनाई जा रही इस दीवार का ऊपरी हिस्सा बीती बारिश में ढह गया था। सिंचाई विभाग नदी में बहाव कम होते ही टूटे हिस्से को दोबारा से बनाने की तैयारी में थी। इसी बीच अब एनआईटी की रिपोर्ट ने सिंचाई विभाग की नींद हराम कर दी है। पीएचई विभाग के द्वारा बनाई जा रही जलप्रदाय योजना के लिए यह दीवार अहम है। दीवार के टूटने के बाद योजना की सफलता के लिए चिंतित पीएचई विभाग ने एनआईटी (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान) से सारे पहलुओं की तकनीकी जांच करवा दी। बीते 4 जनवरी को पीएचई के ईई पंकज जैन के साथ संस्थान के इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख डॉ। इश्तियाक अहमद और डॉ। मणिकांत वर्मा के नेतृत्व में टीम जांच के लिए सुपेबेड़ा और सेनमूड़ा घाट पहुंची थी। टीम ने सप्ताह भर पहले ही अपनी रिपोर्ट में डायफ्राम वॉल को नए सिरे से बनाने की सिफारिश की है। पंकज जैन ने इस रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए बताया कि एनआईटी की रिपोर्ट को

अपने विभाग के आला अफसरों के अलावा जिला कलेक्टर और सिंचाई विभाग के ईई को भेजकर अवगत कराया गया है।

एनआईटी के रिपोर्ट में क्या?

डायाफ्राम दीवार के निर्माण का उद्देश्य यानी नदी के ऊपरी हिस्से में सतह और उपसतह दोनों तरह के पानी की उपलब्धता है। डायाफ्राम दीवार की विफलता के कारण पूरा नहीं होता दिख रहा है। डायाफ्राम दीवार के मध्य भाग में दीवार नदी के बहाव को नहीं झेल सकी और पलट गई। पूरे स्ट्रेक्चर में कई जगहों पर दरारें पड़ गई है। जो खराब कारीगरी को दर्शाता है। दीवार के किनारे किए गए पिचिंग कार्य में बोल्डर ढीले ढंग से रखे गए हैं। नदी के पानी की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया जो मानक अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया था। रेत खनन के कारण तेल नदी तट के दोनों किनारा मिट्टी कटाव के कारण नदी का स्वरूप बदल गया है। पीएचई और डब्ल्यूआरडी (सिंचाई) विभाग के बीच समन्वय की कमी देखी जा रही है।

एनआईटी ने दिए ये सुझाव

डायाफ्राम दीवार की संरचनात्मक विफलता को उचित कामकाज और संरचना की सुरक्षा के साथ तत्काल पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। डायाफ्राम दीवार के निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इसका कुछ हिस्सा या तो पलट गया है या इसमें गहरी दरारें हैं। जिससे पानी आसानी से बह सकता है। जल जीवन मिशन के तहत सुपेबेड़ा जलप्रदाय योजना की सफलता के लिए यह दीवार अहम है। नदी तट पर जलप्रदाय योजना के लिए इंटेक वेल का निर्माण किया जा रहा है। बारह महीने सतत पानी सप्लाई और जल आपूर्ति के लिए मजबूत कार्यक्षमता वाली दीवाल जरूरी है।

ईई बोले एक्सपर्ट से परीक्षण करा रहे

सिंचाई विभाग के ईई एसके बर्मन ने एनआईटी की रिपोर्ट से अनभिज्ञता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वॉल के क्षतिग्रस्त हिस्से में अब भी पानी भरा हुआ है। एक्सपर्ट की विजीट कराई जा रही है। जरूरी हुआ तो नए सिरे से भी निर्माण कराएंगे।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

विस में लगे प्रश्न का समय पर जानकारी नहीं दे पाए अधिकारी

बिलासपुर। विधानसभा में लगे प्रश्नों के लिए सही समय पर जानकारी नहीं देने वाले चार डीईओ को संभागीय संयुक्त संचालक आरपी आदित्य ने नोटिस भेजा है। बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा के जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजकर तीन दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है। मामला डीएमएफ फंड से स्कूलों में किए गए कार्यों से जुड़ा है। दरअसल, विधानसभा सत्र में विधानसभा पूरक प्रश्न क्रमांक 640 में डीएमएफ फंड से जिलेवार स्कूलों में किए गए व्यय की जानकारी मांगी गई थी। 5 फरवरी तक केवल सक्ती, जांजगीर-चांपा, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला पेण्डा मरवाही जिले ने जानकारी दी है। वहीं बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और कोरबा से जानकारी समय पर नहीं भेजी गई थी। जिसे लेकर जेडी ने सभी डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि बिलासपुर संभाग के स्कूलों में स्कूल शिक्षा विभाग को प्राप्त राशि के संबंध में रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने प्रश्न लगाया था।

राम लला के दर्शन पाकर वापस लौटा पहला जत्था

धमतरी। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी के दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसके बाद श्रद्धालुओं का तांता राम लला दर्शन के लिए लगने लगा है। प्रदेश सरकार ने राम लला के दर्शन के लिए विशेष आस्था स्पेशल ट्रेन चलवाई है। जो प्रदेशवासियों को अयोध्या राम मंदिर ले जाकर राम लला के दर्शन करवा रही है। इसी कड़ी में पहली आस्था स्पेशल ट्रेन में अयोध्या गए श्रद्धालुओं की घर वापसी हुई है। धमतरी से अलग-अलग संघठन से 80 श्रद्धालु अयोध्या गए थे। जिनकी वापसी पर बस स्टैंड में भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश से अयोध्या धाम भगवान श्री राम के दर्शन के लिए चलने वाली पहली आस्था स्पेशल ट्रेन 4 फरवरी रविवार को रवाना हुई थी। जिसमें प्रदेश के विहिप, बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता भी गए थे। साथ ही रामकाज में सेवा करने वाले 2000 रामभक्त छत्तीसगढ़ से अयोध्या धाम भगवान श्री राम के दर्शन लाभ प्राप्त करने पहुंचे थे। जिनमें धमतरी जिले के विहिप, बजरंग दल और आरएसएस के पदाधिकारी समेत 80 रामभक्त कार्यकर्ता शामिल हुए।

कोरबा में जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंसा, मचा हड़कंप

कोरबा। कोरबा जिले के पसान क्षेत्र में एक बार फिर से जमीन धंसने की घटना सामने आई है। इस क्षेत्र में इस तरह की यह तीसरी घटना है। कोरबी-चोटिया इलाके में संचालित होने वाली एसईसीएल की विजय वेस्ट भूमिगत कोयला खदान के कारण यह घटना घटी है। पसान क्षेत्र के ग्राम जलके-तनेरा सर्किल के आसपास हुई घटना से करीब तीन फीट चौड़ी और सौ फीट गहरी दरार पड़ गई है, जिसके कारण लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह के समय ग्रामीण मवेशी चराने गए हुए थे। इस दौरान उनकी नजर पड़ी। ग्रामीणों ने गांव पहुंचकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। कुछ ग्रामीणों ने जाकर देखा तो बड़ा हिस्सा धंसा हुआ था। लोगों का कहना है कि इस इलाके में जमीन धंसने की तीसरी घटना है। इससे पहले भी जमीन का बड़ा हिस्सा धंस चुका है। ग्रामीणों की मांग है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस इलाके का सर्वे किया जाए।

कबीरधाम में हिंदू संगम कार्यक्रम के दौरान खूनी झड़प

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोड़ला नगर पंचायत में 5 से 9 फरवरी तक हिंदू संगम का आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार 6 फरवरी को शाम 7.30 बजे मंच पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। अचानक चाकूबाजी हुई। इसमें दो युवकों पर चाकू से हमला किया गया। कबीरधाम एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि हिंदू संगम में दो पक्षों में विवाद हुआ जिसमे एक पक्ष के बहन के साथ छेड़खानी करने की बात को लेकर दूसरे पक्ष योगेश यादव पिता दिनेश यादव, निवासी बांधाटोला (बोड़ला) उसके साथी परदेशी ध्रुवे पिता कुमार ध्रुवे 19 वर्ष बांधाटोला (बोड़ला) के साथ मारपीट हुई। विवाद- मारपीट के दौरान युवक योगेश यादव को सिर में चोट लगी है। डॉक्टर द्वारा धारदार चाकू की चोट बताई गई है। युवक को सात टांके लगे हैं। उसे जिला अस्पताल कवर्धा रेफर किया गया है। देर रात तक इस मामले में तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस घटना के बाद रात के समय कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। मौके पर पुलिस बल तैनात हैं।

टीचर के टॉर्चर से परेशान छठी की छात्रा ने दी जान

अंबिकापुर। अंबिकापुर में एक छात्रा ने मंगलवार की रात कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह रिंग रोड नमनाकला स्थित एक नामचीन मिशन स्कूल में कक्षा छह में पढ़ती थी। आत्महत्या से पहले अंग्रेजी में एक सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें स्कूल की दो शिक्षिकाओं पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा कि मर्सी सिस्टर काफी बुरी और डेंजरस हैं और वह टॉर्चर करती है। मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहीं, घटना से आक्रोशित भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने स्कूल कैंपस के बाहर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल व शिक्षिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं, अभिभावक संघ भी काफी आक्रोशित नजर आए और अध्यक्ष निलेश सिंह की अगवानी में उन्होंने एसपी ऑफिस पहुंचकर दोषी शिक्षिकाओं की तत्काल गिरफ्तारी एवं एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।

कोंडागांव उद्यानिकी विभाग पर भ्रष्टाचार करने का आरोप, विभाग का दावा नियमों के तहत हुआ काम

कोंडागांव। छत्तीसगढ़ सरकार ने डीएमएफ की मदद से पिछड़े इलाकों में ग्रामीणों के साथ क्षेत्र को उन्नत बनाने का प्लान तैयार किया।लेकिन कोंडागांव में उद्यानिकी विभाग पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों का आरोप है कि उद्यानिकी विभाग ने डीएमएफ राशि से जो काम करवाया है।उसका भुगतान नहीं किया गया।उल्टा किसानों को क्रियान्वयन एजेंसी बनाकर उनके पासबुक और चेकबुक पर साइन करवाकर अफसरों ने अपने पास रखे।इसके बाद राशि का आहरण कर लिया। किसानों का आरोप है कि जो काम हुआ उसका भी भुगतान उन्हें नहीं मिला है। वहीं उद्यानिकी विभाग का दावा है कि सारे काम नियम के मुताबिक हुआ हैं।यदि किसी को भी इसमें आपत्ति है या फिर किसी तरह की लापरवाही हुई है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

कोंडागांव जिले में उद्यानिकी विभाग पर डीएमएफ राशि में बंदरबाट करने के आरोप किसानों ने लगाए हैं।जहां केशकाल विकासखंड में ऑयल पाम वृक्षारोपण के काम के लिए डीएमएफ का इस्तेमाल किया

गया।लेकिन किसानों की जानकारी के बिना ही उनके नाम पर खाते खुलवाकर राशि का आहरण करवा लिया गया।किसानों का आरोप है कि जो काम बताया गया था वो पूरा भी नहीं हुआ।वहीं जितने लोगों ने काम किया उनको मजदूरी भी नहीं मिली।

उद्यानिकी के बजाय किसानों को बनाया गया क्रियान्वयन एजेंसी

इस काम के लिए उद्यानिकी विभाग के बजाय किसानों को ही क्रियान्वयन एजेंसी बना दिया। इसके बाद किसानों के नाम से बैंक खाता खुलवाकर रूपए उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया। प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने वाले उद्यान अधीक्षक लोकेश प्रसाद ध्रुव का कहना है कि डीएमएफ मद से ऑयल पॉम पौध रोपण प्रक्षेत्र में फेंसिंग, गेट निर्माण के लिए 2 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि आवंटित की गयी थी। जिसके लिए किसानों का समूह बनाकर उनके समूह के अध्यक्ष के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया।

जिन ग्रामीणों के खाते खुलवाकर पैसों का आहरण किया गया,उन्हें ना तो खाता और ना ही पैसों के बारे में कोई जानकारी है।ईटीवी भारत ने किसानों से जब बात की तो सारा मामला सामने आया। ग्रामीणों के मुताबिक उनके खाते में कितने पैसे आए,कितना व्यय हुआ उन्हें नहीं पता।क्योंकि सभी लोगों के पासबुक,चेकबुक और सील उद्यानिकी विभाग के अफसरों के पास है।

किसान गोकुल राम नेताम ने कहा उद्यानिकी विभाग के अफसरों ने ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर भी करवा लिए हैं। इसलिए कितनी राशि निकाली गयी और किसे दी गई ये नहीं पता है।फेंसिंग और बाउंड्री कार्य में कहीं चार गेट लगाए लगाए जाने थे। वहां दो या तीन गेट ही लगाए गए हैं। साथ ही जाली को लगाने के लिए पोल भी कम लगाए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए उन पर जो पेंट किया जाना था वह भी गायब है।

विभाग का दावा नहीं हुई गड़बड़ी

इस बारे में डिप्टी डायरेक्टर उद्यानिकी विभाग कोंडागांव विमल कुमार गौतम का कहना है कि ऑयल पाम पौधारोपण केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। इसमें 300 हेक्टेयर में पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें कि बयानार, पिटिसपाल, कानागांव, केजंग, चलका, गांव में रोपण हुआ है। जिसमें 124 किसानों के खेतों में लगभग 214 हेक्टेयर में ऑयल पाम पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें 133 हेक्टेयर क्षेत्र में अभी रोपण कार्य किया गया है। इसमें फेंसिंग और गेट निर्माण कार्य जिला खनिज न्यास निधि से हुआ है। इसमें निर्माण एजेंसी सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग कोंडागांव है।

डिप्टी डायरेक्टर विमल कुमार गौतम ने कहा काम में विभाग के नियमों का पालन हुआ है। पहले समूह तैयार किया गया। उसमें एक समूह में 8-10 किसान लिए गए। जिसमें उस समूह के अध्यक्ष-सचिव के खातों में डीबीटी की गयी है। इसमें निविदा की आवश्यकता नहीं थी। किसानों से यदि ब्लेंक चेक पर सिग्नेचर करवाया गया या राशि निकाली गयी थी तो इस संबंध में जांच करवाई जायेगी। मुझे इस सम्बन्ध में अभी जानकारी नहीं है।

इस बारे में सीपीआई के जिला सचिव तिलक पांडे का कहना है कि डीएमफ मद से किसानों के खेतों में ऑयल पाम पौधारोपण प्रक्षेत्र में फेंसिंग और गेट निर्माण कार्य हुआ है। जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। प्रशासन को इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए।

इस पूरे काम में उद्यानिकी विभाग का दावा है कि डीएमएफ राशि को निकालकर काम करवाने में नियमों का पालन हुआ है।लेकिन किसानों ने मजदूरी नहीं मिलने और बिना जानकारी के पैसे निकालने के आरोप लगाए हैं।ऐसे में सच्चाई क्या है इस बात की जानकारी जांच कराने के बाद ही सामने आ पाएगी।

हसदेव का मामला सदन में गूंजा, पेड़ों की कटाई पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव

■ आसंदी ने किया खारिज, गर्भगृह में उतरने पर विपक्षी सदस्य निलंबित

रायपुर। विधानसभा में बुधवार को हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का मुद्दा विपक्ष ने जोर-शोर से उठाया। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग की। स्पीकर डॉ। रमन सिंह के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य करने पर विपक्ष ने हंगामा मचाया। सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिए स्थगित होने के बाद फिर शुरू होते ही विपक्ष ने चर्चा की मांग दोहराते हुए गर्भगृह में उतरकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए। गर्भगृह में उतरने पर विपक्षी सदस्य स्वमेव निलंबित हो गए।

सदन में विपक्ष के चर्चा की मांग दोहराए जाने पर संसदीय कार्यमंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आसंदी की व्यवस्था आने के बाद भी विपक्ष की मांग उचित नहीं। सदन में चर्चा के पर्याप्त मौके मिलेंगे।

इसके पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सदन में कहा कि हसदेव क्षेत्र में सभी कोल ब्लॉक रद्द करने को लेकर इस सदन में ही संकल्प 26 जुलाई 2022 को पारित किया गया था। केंद्र सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार बनने और मुख्यमंत्री बनने के पहले वन विभाग ने हसदेव में 15 हज़ार 307 पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा ने अशासकीय संकल्प पारित कर दिया था, इसके बाद भी इस तरह का आदेश जारी करना दुखद है। ये गंभीर समस्या है। हसदेव ख़त्म होने से बांगो बांध ख़त्म हो जाएगा। वन खत्म हो जाएगा।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसी सदन में सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प पारित किया गया था। इसके बाद भी कटाई की अनुमति दे दी गई। ये कौन सी अदृश्य शक्ति है, जिसमें पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी गई। इससे वन्यजीव प्रभावित होंगे। वहां के आदिवासी प्रभावित होंगे। बांगो बांध प्रभावित होने की वजह से कई जिलों की सिंचाई से प्रभावित होगा।

कांग्रेसी विधायक कुंवर निषाद और विक्रम मंडावी ने कहा कि जंगल ख़त्म होने से जीवन प्रभावित होगा। हसदेव में हाथी मानव द्वन्द चल रहा है। हसदेव क्षेत्र के आदिवासी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पर खतरा मंडरा रहा है।

कांग्रेसी विधायक अनिला भेड़िया ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए जंगल काटा जा रहा है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है। हसदेव को बचाने और आदिवासियों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। अंबिका मरकाम ने कहा कि हमारे

मुख्यमंत्री आदिवासी हैं। हसदेव में आदिवासियों का सबसे बड़ा नुक़सान हो रहा है। हम मानते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने का लाभ मिलता।

अटल श्रीवास्तव ने कहा कि आदिवासियों की ज़मीन उजाड़ने का काम किया जा रहा है। पुलिस के पहरे में पेड़ों की कटाई हो रही है। अदाणी को दिये गये एमडीओ में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि सालों तक कोल का खनन किया जा सकता है, फिर एक नये ब्लॉक की क्या ज़रूरत? लालजीत सिंह राठिया ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री राज्य के आदिवासियों का सुरक्षा कवच हैं। उन्हें आदिवासियों की इस समस्या का निराकरण करना चाहिए। हसदेव की कटाई से बांगो बांध पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।

हर्षिता बघेल और सावित्री मंडावी ने कहा कि हसदेव को केंद्र और राज्य का विषय ना बनाकर आदिवासियों के हित में फ़ैसला लिया जाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हज़ारो सालों से इस जंगल को बचाकर रखा है। ये वन्य जीवों के साथ साथ आदिवासी संस्कृति को ख़त्म करने जैसा है।

राघवेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि हसदेव क्षेत्र के किसानों की कमाई 160 फ़ीसदी बढ़ी है। ये सघन क्षेत्र के जंगल हैं। खड़गवा क्षेत्र में वन अधिकार पट्टे बंटे हैं। राजस्थान के पास पर्याप्त कोयला है। इस भंडार से काम चल सकता है। इसके बाद भी काटने की अनुमति देती है तो ये गंभीर मुद्दा होगा।

बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने हसदेव के लिये उस वक़्त मुझे विशेष अनुमति दिया था, जब वह ख़ुद आसंदी पर बैठे थे। बिसाहू दास महंत, रामचंद्र सिंहदेव जैसे नेताओं ने बांगो बांध की कल्पना की थी। सारे विकास के काम गंगरेल में हो रहे थे, बागों में नहीं हो रहे थे। जो आज आदिवासी हितों को रक्षा की बात कर रहे हैं, उनमें से एक आदमी भी बोलने खड़ा नहीं हो रहा था।

भाजपा विधायक ने कहा कि मैंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी जब मदनपुर आये थे, तब जिस चबूतरे में बैठे थे, वहाँ के किसानों की ज़मीन बेदख़ल करने का आदेश भी पिछली सरकार ने दिया था। पिछली सरकार ने तीन आदेश देकर पेड़ों को आरी देने का काम किया था। ये काम विष्णुदेव साय सरकार ने नहीं किया है। उस दिन मैं चीख-चीख कर कह रहा था कि पेड़ों की कटाई के सभी आदेशों को रद्द कर दिया जाये। उस दिन ही सख़्ती से सरकार अपने सभी आदेशों को रद्द कर देती तो ज़्यादा बेहतर होता। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि यदि आसंदी पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाये तो ये चिंता का विषय है। देश में साढ़े तीन लाख मीट्रिक टन कोयले का भंडार है, जो हसदेव क्षेत्र के बाहर हैं। हसदेव को बचाकर भी कोयले की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। हसदेव में सौ से अधिक प्रकार के वनस्पति हैं। सैकड़ों प्रकार के जीव-जंतु हैं। मुख्यमंत्री का हाथ, ना उधर का शामिल है, ना इधर का शामिल है।

भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने बताया बजट सत्र का महत्व

रायपुर। विधानसभा बजट सत्र को लेकर भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि इस सत्र में प्रदेश की जनता किए हुए वादे हैं, उन्हें पूरा करने के लिए सारी चीज दी गई है, और जो अपेक्षा प्रदेश की जनता का है। चुनाव के समय जो वादे किए हैं, उन सारे वादे को हम लोग पूरा करेंगे। इस लिहाज से बजट सत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। महतारी वंदन योजना को लेकर धरमलाल कौशिक ने कहा कि फॉर्म भरा जा रहा है। हम चाहते हैं कि पात्रता रखने वाले एक भी महिला वंचित न हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके, उनका फॉर्म फिलअप हो सके। इससे लाभ से वंचित न हो, बल्कि उनका लाभ मिलना शुरू हो जाए। इसलिए प्रदेश में काफी उत्सुकता के साथ यह लोग फॉर्म भरा रहे हैं। अयोध्या जाने के लिए दुर्ग से जाने वाली ट्रेन के संबंध में धरमलाल कौशिक ने कहा कि उसे ट्रेन को झंडी दिखाने के लिए हमारे मंत्री दयालदास बघेल, श्याम बिहारी जयसवाल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और मैं स्वयं रहूंगा। हमारे सहयोगी रहेंगे। जितने विधायक सांसद हम सबको आमंत्रित किए हैं, और बड़े संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि साथ शामिल होंगे। हम लोग राम भक्तों का स्वागत करने के बाद में उनको रवाना करेंगे। प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर कौशिक ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव है। और लोकसभा के चुनाव में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, इसलिए आचार संहिता लगने के पहले जो पूर्व तैयारी होनी चाहिए, हम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश प्रभारी बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रहे हैं, जिसके कारण में वह लगातार आते रहेंगे। हमारे बीच में रहेंगे। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव मार्गदर्शन में जीते हैं। हम इस बार 11 के 11 सीट उनके मार्गदर्शन में जीतेंगे। 9 फरवरी बजट पेश करने को लेकर धरमलाल कौशिक ने कहा कि जो प्रदेश की जनता के गांव है गरीब हैं, किसान हैं। खास करके हमारे युवा साथी हैं, महिलाएं हैं। इन सभी को समाहित करते हुए बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत होगा। जो रुके हुए विकास के कार्य हैं, अवरुद्ध कार्य हैं, उसकी गति मिल सके, बढ़ावा मिल सके। इस प्रदेश को ऊंचाइयों में लेकर आया सके। उसके अनुरूप हमारा बजट प्रस्तुत होगा।

संक्षिप्त समाचार

हाईकोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव को जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 20 मार्च को

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को एक चुनाव याचिका को लेकर नोटिस जारी किया है। यह याचिका भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला और देवाशीष तिवारी के जरिए लगाई है। याचिका में बताया गया है कि देवेंद्र यादव के निर्वाचन हलफनामे में संपत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एवं आपराधिक मामले छिपाए गए हैं। इसी को आधार बनाकर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी को दबाया जाना जन प्रतिनिधि कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिससे उम्मीदवार का निर्वाचन अवैध हो जाता है।

मुख्यमंत्री ने पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती वीणा वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्यसभा की पूर्व सांसद श्रीमती वीणा वर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्रीमती वर्मा का कल नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्रीकांत वर्मा की पत्नी थीं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार जनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

सरकार की जनकल्याणकारी योजना से रूबरू होंगे लोग

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने सुसज्जित एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस एलईडी स्क्रीन वैन को जनसंपर्क विभाग ने तैयार कराया है। यह वैन अगले एक महीनें तक रायपुर जिले की एक सौ से अधिक ग्राम पंचायतों और हाट-बाजारों में पहुंचकर लोगों को सरकार की जनहितकारी योजनाओं से रूबरू कराएगी। योजनाओं को छोटी-छोटी फिल्मों के माध्यम से बताया जाएगा। एलईडी में शासकीय योजनाओं के वीडियो दिन में सूर्य के प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देंगे।

छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल सरकार: दीपक बैज

■ पीसीसी चीफ बोले- भाजपा ने कोल माइंस के बहाने आदिवासियों से छीनी जल, जंगल और जमीन

रायगढ़। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेसियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कल 8 फरवरी को राहुल गांधी ओडिशा के कनकतुरा से रायगढ़ के सीमांत गांव रेंगालपाली में प्रवेश करेंगे। यात्रा से पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार के 2 महीने के कार्यकाल पर जमकर निशाना साधा है। दीपक बैज ने कहा, विष्णुदेव साय की सरकार दिल्ली की रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार है।

बैज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के ओएसडी से लेकर ऑफिस बीयरर तक दिल्ली से नियुक्त किए गए हैं। इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि विष्णुदेव साय की सरकार कितनी बेबस और लाचार है। पिछले दो महीनों में प्रदेश में किसी भी वर्ग के लिए कोई विकास कार्य नहीं हुआ है।

दीपक बैज ने कहा कि यही हालत राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी है। वहां की सरकारें भी दिल्ली से ही रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही हैं। भाजपा पर बुल्डोजर कल्चर का

आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को नियम कानून से कम करना चाहिए। एक व्यक्ति के गलती या अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। बैज ने कहा बीजेपी ने आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन भी कोल माइंस के बहाने छीना है।

ओमान में बंधक भिलाई की दीपिका, बैज ने विदेश मंत्री और साय को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ के भिलाई की महिला दीपिका जोगी की मदद के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने विदेश मंत्री और प्रदेश के मुखिया को पत्र लिखा है। ओमान के मस्कट में बंधक बनाई गई महिला की मदद के लिए उन्होंने कदम उठाया है। पीसीसी चीफ ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीएम विष्णुदेव साय, मुख्य सचिव, डीजीपी छत्तीसगढ़ पुलिस, जिलाधीश दुर्ग, पुलिस अधीक्षक दुर्ग को पत्र लिखा है।

पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि समाचार माध्यमों में यह खबर प्रसारित हुई है कि हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की एक महिला जो कि भिलाई जिला दुर्ग की निवासी है। वह 30 मई 2023 को केरल की एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से हाउस मेड का काम करने ओमान की राजधानी मस्कट भेजी गई थी। उस महिला ने अपना एक वीडियो भेजकर बताया है कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा, प्रताड़ित किया जा रहा। उसे घर वापस नहीं आने दिया जा रहा, वहां पर जिनके यहां वह काम करती है उसकी मालकिन धमका रही है कि 3 लाख रुपये दो वारन दूसरे को बेचकर पैसा वसूलेंगे।

बैज ने कहा कि मामला बेहद ही गंभीर है। देश की और हमारे प्रदेश की एक महिला विदेश में संकट में फंसी है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर उक्त महिला दीपिका जोगी को तत्काल स्वदेश वापसी के प्रबंध सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।

नेता प्रतिपक्ष महंत ने उठाया मरवाही वनमंडल में अनियमितता का मामला

रायपुर। मरवाही वनमंडल के अंतर्गत अनियमितता का मामला सदन में उठा। नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरणदास महंत के सवाल के जवाब में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि ये पूरा मामला हमारे संज्ञान में आया है। सभी मामलों में जल्द से जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई की जाएगी।

नेता प्रतिपक्ष डॉ। चरणदास महंत मामला उठाते हुए कहा कि लिखित जवाब में कहा गया है कि 72 प्रकरण जांच के लिए लंबित हैं। लगभग 40 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। ये मेहरबानी किसके लिए है। पुराने मुख्यमंत्री के लिए?, नये मुख्यमंत्री के लिए है?, या किसी और के लिए है? महंत ने कहा कि 2020 में सिर्फ़ छह शिकायतों की बात हुई थी। तब कहा गया था कि 15 दिनों में जांच कर ली जाएगी। इस प्रकरण में विभाग के अधिकारी उत्तरदायी हैं। ज़िम्मेदार कौन है? मेहरबानी किसके लिये की जा रही है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि 79 मामले सामने आये थे। 7 मामलों में जांच प्रक्रियाधीन हैं। बाक़ी 72 मामलों में जांच आने वाले छह महीनों के भीतर कर ली जाएगी। 7 मामलों में 35 अधिकारियों को दोषी पाया गया है। बीजेपी विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। मरवाही इकलौता वन मंडल था, जहां रेंजर और एसडीओ, डीएफ़ओ के पद पर बैठे थे। ये इतना बड़ा मामला है कि जांच के लिये दुबई तक जाना होगा। ईडी की तरह जांच विस्तृत करना होगा।

महतारी वंदन योजना: ऑनलाइन आवेदन न करें और फर्जी वेबसाइटों से बचें

■ 20 फरवरी तक होगा ऑफलाइन आवेदन

जगदलपुर। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आर्थिक स्वालंबन सहित उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए महतारी वंदन योजना 2024 लागू की गई है। इसके तहत बस्तर जिले में 5 फरवरी से 20 फरवरी तक सभी निकायों एवं ग्राम पंचायतों में आयोजित विशेष शिविरों में आवेदन लेना शुरू हो गया है। अभी सभी निकायों एवं ग्राम पंचायतों में ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

जगदलपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि योजना को लेकर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। फर्जी साइट https://www.mahatarivandanyoujna.info/beneficiary&apply नाम से वायरल हो रहा है। फर्जी साइट में कोई भी हितग्राही अपना फॉर्म न भरें। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि महतारी वंदन योजना वर्तमान

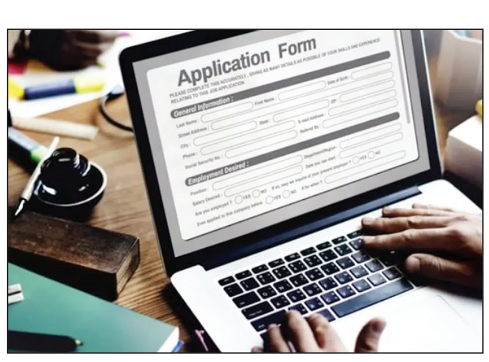

में नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में जाकर ऑफलाइन आवेदन भरा जा सकता है।

उक्त विशेष शिविरों में आवेदन पत्र भरने के लिए स्थानीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए निवासरत क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, परियोजना कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय, नगर पंचायत, नगर निगम कार्यालय अथवा जिला कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं तथा सही जानकारी प्राप्त कर फॉर्म भर सकते हैं।

महतारी वंदन योजना का लाभ लेने महिलाओं की उमड़ी भीड़

रायपुर। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन भरने का सिलसिला जारी है। फॉर्म भरने के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस योजन को लेकर महिलाएं काफी उत्साहित हैं। प्रदेशभर में बीते दो दिनों सात लाख 77 हजार 905 आवेदन जमा किया गया है। दूसरे दिन 5 लाख 96 हजार से अधिक महिलाओं ने आवेदन जमा किया। अब तक सबसे ज्यादा 61 हजार 994 आवेदन जांजगीर जिले में भरे गए हैं। इसके बाद महासमुंद जिले में 60 हजार 187 और दुर्ग जिले में 56 हजार 826 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

प्रदेशभर में महतारी वंदन योजना का माहौल है। आवेदन भरने को लेकर सभी जिलों में लग रहे कैंपों में महिलाओं की भीड़ उमड़ी हुई है। इस योजना के लाभ को लेकर महिलाओं में बेहद उत्साह है। महिलाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि से वह अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से सहजता से आवेदन प्राप्त करने और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन के लिए सभी जिलों में कलेक्टरों के निर्देशन में बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रक्रिया में अधिक समय न लगे इसके लिए प्रशासन ने पात्रता संबंधी नियमों को बताने और जरूरी दस्तावेज चेक करने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू

रायपुर। छत्तीसगढ़ शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसिलिंग जारी है। तीसरे चरण के बाद अब चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग कल यानी 8 फरवरी से शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट से जुड़ना होगा। बता दें कि चतुर्थ चरण की ऑनलाइन काउंसिलिंग 8 फरवरी दोपहर 12 बजे से 10 फरवरी शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in के माध्यम से अभ्यार्थी शामिल हो सकते हैं। निर्धारित समय पर अभ्यर्थी विभाग की ओर से दिए गए लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। काउंसिलिंग में व्यापम की परीक्षा परिणाम के अनुसार शिक्षक पद के कटऑफ रैंक की पूरी जानकारी विभाग के पोर्टल https://eduportal.cg.nic.in पर देख सकते हैं। उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस काउंसिलिंग में कुल 1342 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। शालाओं के आबंटन बाद अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन आबंटित संभाग के कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बस्तर/सरगुजा में किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बलरामपुर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
eProcurement portel : https://eproc.cgstate.gov.in
(द्वितीय आमंत्रण)
शुद्धि पत्र क्रमांक 01

निविदा सूचना क्र. 21 एवं 22/व.ले.लि./ ई-प्रोक्योरमेंट / 2023-24, सिस्टम क्र. 151703 एवं 151704 दिनांक 16.01.2024, विज्ञापन क्र. 07174 एवं निविदा सूचना क्र. 23 एवं 24/व.ले.लि./ ई-प्रोक्योरमेंट / 2023-24, सिस्टम क्र. 151709 एवं 151714 दिनांक 17.01.2024, विज्ञापन क्र. 07210 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

स.क्र.	विवरण	पूर्व प्रस्तावित निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि	पूर्व प्रस्तावित निविदा खुलने की तिथि	संशोधित निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि	संशाधित निविदा खुलने की तिथि
1.	सिस्टम क. 151703 निविदा सूचना क / 21 / 2023-24, 16.01.2024	02-02-2024 17:30 बजे	05-02-2024 11:30 बजे	09.02.2024 17:30 बजे	12-02-2024 11:30 बजे
2.	सिस्टम क.151704 निविदा सूचना क / 22 / 2023-24, 16.01.2024	02-02-2024 17:30 बजे	05-02-2024 11:30 बजे	09.02.2024 17:30 बजे	12-02-2024 11:30 बजे
3.	सिस्टम क.151709 निविदा सूचना क / 23 / 2023-24, 17.01.2024	05-02-2024 17:30 बजे	06-02-2024 11:30 बजे	12.02.2024 17:30 बजे	13-02-2024 11:30 बजे
4.	सिस्टम क.151714 निविदा सूचना क / 24 / 2023-24, 17.01.2024	05-02-2024 17:30 बजे	06-02-2024 11:30 बजे	12.02.2024 17:30 बजे	13-02-2024 11:30 बजे

पूर्व प्रकाशित विज्ञापन क. :- जी - 07174 , एवं जी - 07210.
निविदा की अन्य शर्ते एवं विवरण यथावत रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग बलरामपुर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

जी-07570/9

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़)
E-Mail dfo_balodabazar@rediffmail.com, ph: 07727-223526

नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि बलौदाबाजार वनमण्डल बलौदाबाजार के निस्तार / उपभोक्ता / अस्थाई पड़ाव डिपो में संग्रहित जलाऊ चट्टा/व्यापारिक बांस / औद्योगिक बांस / फेसिंग पोल्स /बल्ली के निर्वर्तन हेतु नीलाम दिनांक 14.02.2024 को महासमुंद वनमण्डल अंतर्गत पिथौरा काष्ठागार में नीलाम सुबह 09:00 बजे से प्रारंभ किया जावेगा।

वनोपज की अनुमानित मात्रा

क्र.	डिपो का नाम	नीलाम में रखी जाने वाली वनोपज					
		जलाऊ चट्टा		व्यापारिक बांस		औद्योगिक बांस	
		पुराना	नया	पुराना	नया	पुराना	नया
1	सरसींवा डिपो	40	556	-	-	-	-
2	बरपाली डिपो	-	80	-	4649	-	-
3	थरगांव डिपो	-	-	-	2690	-	-
4	निस्तार डिपो महराजी	-	-	-	1720	-	-
5	अ.प. देवपुर	-	-	-	46000	-	-
6	अ.प.सलिहा	-	-	-	21600	-	-
7	अ.प.नवागांव	-	-	800	58000	312.726	-
8	भाटापारा डिपो	-	-	2540	-	-	-
	योग :-	40	636	3340	134659	312.726	-

टीप:- किसी भी व्यक्ति को नीलाम में बोली लगाने के पूर्व नीलाम के शर्तों का पालन करने के करार के प्रतिक स्वरूप विक्रय सूचना पर अपना हस्ताक्षर करना होगा तथा प्रत्येक लॉट के संबंध में बोली लगाने के पूर्व जिस सीमा तक वह बोली लगाना चाहता हो उसके 10 प्रतिशत के बराबर राशि या 1000/- रूपये इनमें से जो अधिक हो कि बयाने की राशि जमा करना होगा। क्रेता कृपया अपना पेन नंबर एवं जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति वनमण्डल कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। ताकि आयकर संबंधी फार्म पूर्ति हो सकें। 5 लाख या 5 लाख के अधिक खरीदी करने वाले केता को जी.एस.टी. एवं पेन नंबर देना अनिवार्य है।
दूरभाष एवं फैक्स नंबर 07727......9039268076

वनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

जी-07582/6

पाकिस्तान के नेताओं का भारत से रिश्ता

विवेक शुक्ला

पाकिस्तान में संसदीय चुनाव 8 फरवरी को होने हैं। अजीब इत्तफाक है कि अभी तक कोई भी दल अपनी सभाओं में भारत को 'सबक सिखाने' या उससे 'संबंध सुधारने' जैसी बातें नहीं कर रहा। मगर भारत वहां के सभी प्रमुख दलों में किसी ना किसी रूप में मौजूद है। मुस्लिम लीग (एन) के नवाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के बिलावल भुट्टो और जेल में बंद तहरीके इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के नेता इमरान खान का भारत से पारिवारिक संबंध है। इनके अलावा, अवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) और मुत्ताहिदा कौमी पार्टी (एमक्यूएम) का भी भारत या यहां के कुछ शहरों से भावनात्मक संबंध है। नवाज के पुरखे अमृतसर के करीब स्थित जट्टी उमरा गांव से हैं। उनके छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ 2013 में भारत यात्रा के दौरान अपने पुरखों के गांव भी गए थे। नवाज के पिता मोहम्मद शरीफ 1947 से पहले ही कामकाज के सिलसिले में लाहौर चले गए थे। पिता के साथ नवाज 1964 में जट्टी उमरा आए। शरीफ परिवार की स्टील कंपनी 'इत्तेफाक' का भारत की जेएसडब्ल्यू स्टील से बिजनेस संबंध है। वहीं, बिलावल भुट्टो ने मुंबई के कैथेड्रल स्कूल का नाम मां बेनजीर भुट्टो से जरूर सुना होगा। 1947 में जब पाकिस्तान बना, तब बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो इस स्कूल से निकल चुके थे। भुट्टो परिवार 1950 में पाकिस्तान शिफ्ट हुआ। भुट्टो जब मुंबई में स्कूली शिक्षा ले रहे थे तो उनके परम मित्र थे पीलू मोदी। पीलू बाद में राज्यसभा के सदस्य बने। जुल्फिकार के पिता सर शाहनवाज भुट्टो देश के विभाजन से पहले जूनागढ़ रियासत के प्रधानमंत्री थे। भुट्टो की मां हिंदू थीं। उनका निकाह से पहले नाम लक्खीबाई था, बाद में हो गया खुर्शीद बेगम। जब बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई, तब जूनागढ़ शहर की जामा मस्जिद में उनकी आत्मा की शांति के लिए नमाज अदा की गई थी। मशहूर क्रिकेटर और पीटीआई लीडर इमरान खान को अलग-अलग केसों में लंबी सजा हो चुकी है। इमरान के नाना डॉ. इकरामउल्ला खान जालंधर के जाने-माने शिक्षाविद थे। उनका घर था बस्ती दानिशमंदा में। उन्होंने ही जालंधर में इस्लामिया कॉलेज की स्थापना की थी। इमरान 2007 में दिल्ली आए तो उन्होंने मुझे बताया था, 'मेरे नाना का परिवार करीब 500 साल से जालंधर में बसा था। मगर विभाजन के कारण वे लोग लाहौर चले गए। मैं 1983 में नाना का घर देखने जालंधर गया भी था।' उधर, भारत से गए मुसलमानों के हक के लिए लड़ने वाली एमक्यूएम के प्रत्याशी कराची और सिंध में कुछ सीटें जीत सकते हैं। कराची की गुलशन-ए-इकबाल सीट से प्रत्याशी डॉ. खालिद मकबूल सिद्दिकी या एमक्यूएम के दूसरे नंबर के नेता जब अपनी सभाओं में यूपी या भारत का जिक्र करते हैं, तो उन्हें सुनने वाले खुश होते हैं। एक दौर में इसके एकछत्र नेता अल्ताफ हुसैन खुद को आगरा वाला बताया करते थे। वह अब लंदन में निर्वासित जीवन गुजार रहे हैं। अल्ताफ 2004 में दिल्ली में एक सेमिनार में शिरकत करने आए थे। तब उन्होंने कहा था, 'कोई बड़ा मनहूस दिन होता है, जब मेरे घर में यूपी, आगरा, अलीगढ़ वगैरह की बातें नहीं होतीं।' पाकिस्तान में अवामी नैशनल पार्टी (एएनपी) का सीमांत गांधी से संबंध रहा है। सीमांत गांधी के बेटे खान अब्दुल वली खान ने इसकी स्थापना की थी। दादा वली खान और पिता की तरह इसके वर्तमान नेता अफसंदयार वली खान भारत के मित्र हैं। अफसंदयार के दादा और पिता ने देश के बंटवारे का विरोध किया था। एएनपी को इस चुनाव में खैबरपख्तूख्वाह प्रांत में बड़ी सफलता की उम्मीद है। पाकिस्तान में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के नेता मौलाना फजल-उर-रहमान ने 22 दिसंबर, 2013 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत-उल-हिंद के एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। उनका जमीयत-उल-हिंद के नेता महमूद मदनी ने हजारों-लाखों लोगों से परिचय कराया। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराने में मौलाना का खास रोल था। देश के बंटवारे के बाद पाकिस्तान में जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम बनी। फिर इसी नाम से वहां एक सियासी जमात भी बनी। मौलाना उसके नेता हैं।

परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद पर जंग

अजय सेतिया

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के जवाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव का राजनीतिक एजेंडा सेट कर दिया है। वैसे तो राम जन्मभूमि मन्दिर का बनना और 370 का हटना 2024 के लोकसभा चुनावों के मुख्य मुद्दे होंगे, जिन पर देश की जनता वोट करेगी। लेकिन मोदी ने अपने भाषण में तीन ज्वलंत मुद्दे उठाए, जिनमें से दो मुद्दे उनके अपने थे, जबकि तीसरा मुद्दा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी का था। ये तीनों मुद्दे चुनावों में बड़े मुद्दे हो सकते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का चुनावी मुद्दा जाति आधारित जनगणना है।

कांग्रेस ऐसा मानती है कि इस मुद्दे के माध्यम से वह पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को हिन्दुओं से अलग करके चुनावी नैया पार कर सकती है। मोदी और भाजपा इसे हिन्दुओं की एकता को तोड़ने की साजिश के रूप में देखते है। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस के इस मुद्दे का जवाब दिया, तो दूसरी तरफ परिवारवाद की राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग के दोनों मुद्दों को जानदार ढंग से पेश करके समूचे इंडी एलायंस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के आरोप में सजायाफ्ता नेता इंडी एलायंस का नेता है। वह लालू यादव का जिक्र कर रहे थे, जो इंडी एलायंस की हर बैठक में शामिल हो रहे हैं, वह चारा घोटाले में सजा काट चुके है, चारा घोटाले के ही एक अन्य मामले में सजा भुगत रहे हैं और पैरोल पर रिहा हैं। मोदी की ओर से देश की जनता के सामने पेश किए गए इस एक उदाहरण से इंडी एलायंस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। लालू यादव का पूरा कुनबा रेलवे में नौकरियों के बदले गरीबों की जमीनें अपने नाम करवाने के आरोपों में भी चार्जशीटेड है।

लालू यादव खुद और उनका कुनबा परिवारवाद और भ्रष्टाचार का एक ऐसा उदाहरण है, जो जातिवाद की राजनीति के चलते बिहार में भले ही अपनी जमीन बनाए हुए हैं, लेकिन सारे देश में इंडी एलायंस के लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस एक उदाहरण से मोदी ने इंडी एलायंस के उस प्रचार का भी जवाब दे दिया कि सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टेक्स विभाग का अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष की ओर से राजनाथ सिंह और अमित शाह का उदाहरण देकर परिवारवाद की राजनीति के आरोपों का जवाब दिया जाता है। इससे पहले प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर का भी उदाहरण दिया जाता था। मोदी जब भी परिवारवाद की राजनीति पर हमला करते हैं, कांग्रेस असहज हो जाती है। कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के बचाव में उतर आते हैं। सदन में भी जब मोदी ने परिवारवाद पर हमला बोला, तो कांग्रेस के सांसदों ने राजनाथ सिंह और अमित शाह का उदाहरण दिया। राजनाथ सिंह के दो बेटे हैं, पंकज सिंह और नीरज सिंह। बड़ा बेटा पंकज सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा का सदस्य है। वह बीस साल से भारतीय जनता युवा मोर्चे और भाजपा में सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें पहली बार 2017 में विधानसभा का टिकट दिया गया।

अमित शाह का बेटा जय शाह फिलहाल तो राजनीति में नहीं है, फिर भी उसका नाम लिया गया। वैसे तो देश के ज्यादातर नागरिक समझते हैं कि मोदी जब परिवारवाद की राजनीति की बात करते हैं, तो उनके कहने का क्या मतलब होता है, लेकिन जब कांग्रेस के सांसदों ने राजनाथ सिंह और अमित शाह की बात की, तो मोदी ने इसे विस्तार से समझा दिया कि परिवारवाद की राजनीति क्या होती है। यह जवाब राहुल गांधी को भी दिया गया है, जिन्होंने ब्रिटेन में परिवारवाद की राजनीति पर पूछे गए सवाल में यही जवाब दिया था, जो कांग्रेसी सांसदों ने सदन में दिया। वैसे तो उनका यह एक लाईन का जवाब काफी था कि राजनाथ सिंह और अमित शाह की अपनी पार्टियां नहीं हैं। लेकिन उन्होंने विस्तार से समझाया कि एक परिवार से एक नहीं चाहे दस लोग राजनीति में आएं, इससे लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं होता। लोकतंत्र को खतरा तब होता है, जब राजनीतिक पार्टियों पर एक परिवार का कब्जा हो जाता है, इसे परिवारवाद की राजनीति कहते हैं। जैसे तेजस्वी यादव की राजद, अखिलेश यादव की सपा, स्टालिन की द्रमुक, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राहुल गांधी की कांग्रेस, सुखविंदर सिंह बादल का अकाली दल, हेमंत सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा। इन सभी नेताओं को पार्टियां और उनका नेतृत्व अपने पिता से विरासत में मिला।

परिवारवाद और भ्रष्टाचार के बाद नरेंद्र मोदी ने जातिवाद की राजनीति पर हमला किया। कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी ने जाति आधारित राजनीति को 2024 के लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बना लिया है। नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस के जाति आधारित राजनीति के जवाब में कहते रहे हैं कि वह देश में गरीब और अमीर दो ही जातियां मानते हैं, उन्होंने अपने जवाब को धारदार बनाते हुए कहा कि उन्हें सबसे बड़ा ओबीसी दिखाई नहीं देता, जिसे देश ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। राहुल गांधी ने इसके जवाब में ट्विट करके लिखा कि प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश में सिर्फ दो जातियां हैं - अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को %सबसे बड़ा ओबीसी% बताया। किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। मोदी ने कब किसी को छोटा और बड़ा कहा था, असल में राहुल गांधी को जितना समझाया जाता है, उनका हर जवाब और हर टिप्पणी उसी के इर्दगिर्द रहती है। राहुल गांधी ने अपने ट्विट में आगे कहा कि ओबीसी हों, दलित हों या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हैं, तो गिनती से क्यों डरते हैं?

राहुल गांधी के इस जातिवादी भडकाऊ राजनीति के दो जवाब हैं, एक जवाब तो इंडी एलायंस के नेता अखिलेश यादव और इंडी एलायंस के पूर्व नेता नीतीश कुमार दे चुके हैं। इन दोनों ने राहुल गांधी से पूछा है कि आज़ादी के बाद उनकी पार्टी की सरकारों ने 1951 में जाति आधारित जनगणना बंद क्यों करवाई थी। 1961, 1971, 1981, 1991 और 2011 में जनगणना के समय भी कांग्रेस की सरकारें थीं, तब पिछड़ी जातियों, दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय कौन कर रहा था। राहुल गांधी और कांग्रेस के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के साथ इन्साफ की राजनीति में हकीकत होती तो पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडी एलायंस से बाहर क्यों निकलते। क्योंकि पिछड़ी जाति के नेता, चाहे वह अखिलेश यादव हों, या नीतीश कुमार, वे जानते हैं कि राहुल गांधी का जाति आधारित जनगणना का एजेंडा बाकी सब एजेंडे फेल हो जाने के कारण चुनावी एजेंडा मात्र है।

दूसरा जवाब नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दिया, जब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि (जनसंघ के समर्थन से) वह 1970 में अति पिछड़ी जाति के देश में पहले मुख्यमंत्री बने थे, जिनकी सरकार को कांग्रेस ने अस्थिर किया था। कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने पिछले महीने ही सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। राहुल गांधी जब जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, तो वह केंद्र सरकार के सचिवों का उदाहरण देकर कहते हैं कि वहां सिर्फ दो सचिव हैं। इसी के जवाब में मोदी ने कहा है कि वे गिनती करते रहते हैं कि सरकार में कितने ओबीसी हैं। क्या आप (कांग्रेस) यहां सबसे बड़ा ओबीसी नहीं देख सकते? मोदी ने यह इसलिए कहा था क्योंकि अफसरों का काम सरकार के फैसलों का क्रियान्वयन करना होता है, फैसले अफसर नहीं, चुनी हुई सरकारें लेती हैं, और सरकार का मुखिया ही ओबीसी जाति से है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद्

यह उपनिषद् सामवेदीय परम्परा से सम्बद्ध है। महत् स्वरूप वाली यह महोपनिषद् श्री शुकदेव जी एवं महाराज जनक तथा ऋभु एवं निदाघ के प्रश्नोत्तर रूप में प्रकट हुई है। इसमें कुल छः अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम नारायण की अद्वितीयता एवं ईशत्व का विवेचन है। तदुपरान्त यज्ञीय स्तोम की उत्पत्ति, चौदह पुरुष एवं एक कन्या की उत्पत्ति, पच्चीस तत्त्वात्मक पुरुष की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति, चतुर्मुख ब्रह्मा की उत्पत्ति, व्याहृति, छन्द, वेद और देवताओं की उत्पत्ति, नारायण की विराट् रूपता तथा नारायण की उपलब्धि का स्थान हृदय बताया गया है। द्वितीय अध्याय में शुकदेव के स्वयं उद्भूत पारमार्थिक ज्ञान-तत्त्वज्ञान के होते हुए भी शुकदेव की अविश्रान्ति, व्यास जी के उपदेश के प्रति शुकदेव का अनादर, शुकदेव का जनक के पास जाना, जनक द्वारा शुक की परीक्षा, शुक-जनक संवाद, बन्धन-मोक्ष का विवेक, जीवन्मुक्त स्थिति, विदेहमुक्त स्थिति, शुकदेव के भ्रम का निवारण तथा शुकदेव को विश्रान्ति की प्राप्ति आदि विषयों का विवेचन है। तृतीय अध्याय का शुभारम्भ निदाघ के विचार के साथ हुआ है। तदुपरान्त प्रपञ्च (जगत) का अनित्यत्व, अहंकार, तृष्णा आदि की अनर्थकता, देह तथा उसकी अवस्था की निन्दा, संसार की दुःखमयता, स्त्री निन्दा, दिशाओं आदि की क्षणभंगुरता तथा वैराग्य से तत्त्व जिज्ञासा आदि विषय व्याख्यायित हैं। चतुर्थ अध्याय में मोक्ष के चार उपाय, शास्त्रादि द्वारा आत्मावलोकन विधि, समाधि का स्वरूप, जीवन्मुक्त स्थिति, शम, सन्तोष, आत्मविश्रान्ति से कृतकृत्यता, दृश्य जगत् का मिथ्यात्व, आसक्ति तथा अनासक्ति से बन्धन और मोक्ष की स्थिति, संसार की मनोमयता, चैतन्य की अनुभूति ही समाधि, शान्त मनः स्थिति से ब्रह्म प्राप्ति, वासना के परिहार से मोक्ष की प्राप्ति, बन्ध-मोक्ष का मूल संकल्प तथा अनात्माभिमान के त्याग की विधि इत्यादि विषयों का विशद विवेचन किया गया है।

क्रमशः ...

सुरक्षित इंटरनेट दिवस

विकास

लगातार विकसित हो रहे डिजिटल युग में, इंटरनेट सुरक्षा के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। प्रत्येक वर्ष 8 फरवरी को मनाया जाने वाला सुरक्षित इंटरनेट दिवस, व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों के लिए डिजिटल दुनिया को सभी के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए एकजुट होने के वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसे ईयू सेफ बॉर्डर्स द्वारा शुरू किया गया था और बाद में जागरूकता केंद्रों के इनसेफ नेटवर्क द्वारा अपनाया गया था। इस पहल का उद्देश्य इंटरनेट सुरक्षा के महत्व को उजागर करना और जिम्मेदार डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। 2012 में, संयुक्त राज्य

अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर सुरक्षित इंटरनेट दिवस को अपनाया, जो एक वैश्विक आंदोलन में इसके विस्तार का प्रतीक था। आज, सुरक्षित इंटरनेट दिवस भौगोलिक सीमाओं को पार कर दुनिया भर के देशों को ऑनलाइन सुरक्षा और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए एकजुट कर रहा है।

ऐसे युग में जहां डिजिटल इंटरैक्शन दैनिक जीवन का एक बुनियादी पहलू है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस इंटरनेट सुरक्षा पर जागरूकता और शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह हमारी डिजिटल आदतों का मूल्यांकन करने, मजबूत सुरक्षा उपायों को लागू करने और एक सम्मानजनक और समावेशी ऑनलाइन समुदाय की वकालत करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इस दिन को मनाने से यह संदेश पुष्ट होता है कि इंटरनेट सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, जिसमें ऑनलाइन खतरों को कम करने और सकारात्मक डिजिटल परिदृश्य को बढ़ावा देने के लिए उपयोगकर्ताओं, तकनीकी कंपनियों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

इन तरीकों से बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से

जल्द पैसे कमाने की लालच में न फंसे: कई बार पैसों की लालच या सही जानकारी से वंचित रह जाने के कारण लोग आनलाइन मनी फ्राड का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में हमेशा पहले पता करे कि पैसों का लेन देन केवल अपने बैंक के प्रामाणिक ऐप पर ही हो।

खतरे में डाल सकती हैं अनजान लिंक: अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करें और संदिग्ध वेब पेज को तुरंत ही ब्लाक कर रिपोर्ट करें।

बच्चों के ऊपर रखें निगरानी: पेरेंटल कंट्रोल ऐप से बच्चों पर नज़र रखें। सेफ मोड को आन रखें, ताकि सारे वयस्क साइट बच्चों की पहुंच में न आएं।

साइबर स्टाकिंग से रहें सुरक्षित: उन्हीं सुरक्षित ऐप्स का उपयोग करे जो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल आफ इंडिया द्वारा अनुमोदित हैं। कई बार लोकल ऐप के जरिए धोखे से अनुमति ले ली जाती हैं। जिससे अपराधी लोकेशन, कांटेक्ट को ट्रैक कर स्टाकिंग का शिकार बनाते हैं।

इंडी गठबंधन में छोटे चौधरी का बड़ा खेला

नीरज कुमार दुबे

विपक्ष के इंडी गठबंधन की नाव डूबती देख इस पर सवार राजनीतिक दलों में कूद कर अपनी जान बचाने की होड़ देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन की नाव को जिन नीतीश कुमार ने तैयार किया था वही सबसे पहले यहां से दूसरी तरफ कूद गये जिससे नाव का संतुलन गड़बड़ा गया। मौका देख ममता बनर्जी ने भी इस नाव से दूरी बना ली और अब राष्ट्रीय लोक दल भी इससे कूदने के लिए पूरी तरह तैयार है। आम आदमी पार्टी भी इंडी गठबंधन की नाव से कूदने के लिए अपना सामान समेट रही है। इस गठबंधन में अब जो दल बचे हैं वह या तो आपस में ही लड़ रहे हैं या उन दलों के भीतर ही भितरघात देखने को मिल रही है जिसके चलते किसी का चुनाव चिह्न खतरे में पड़ गया है तो किसी की पार्टी का मालिकाना हक किसी और के पास चला गया है। विपक्ष की यह स्थिति देख अब प्रधानमंत्री मोदी के संसद में दिये गये संबोधन की वह बात किसी को अतिश्योक्ति नहीं लग रही कि भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों में अकेले दम पर 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 के पार जायेगा।

विपक्षी गठबंधन की हालत से देश के सामने एक बात और स्पष्ट हो गयी है कि बेमेल विचारधारा वाला यह गठबंधन सिर्फ सत्ता स्वार्थ के लिए बना था। जहां तक राष्ट्रीय लोक दल की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका भाजपा के साथ आना तय हो चुका है। एकाध दिनों में इसकी घोषणा हो सकती है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि राष्ट्रीय लोक दल का भाजपा में विलय भी संभव है लेकिन अगर विलय नहीं हुआ तो गठबंधन होना पक्का है। हम आपको याद दिला दें कि भाजपा ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन का प्रयास उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी किया था लेकिन तब जयंत चौधरी ने साथ आने से मना कर दिया था। राष्ट्रीय लोक दल 2014 से सभी चुनाव विपक्षी दलों के साथ मिलकर लड़ा है लेकिन इसका उसे कोई ज्यादा लाभ

नहीं हुआ। हालांकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में जरूर समाजवादी पार्टी से गठबंधन का रालोद को फायदा हुआ था साथ ही सपा कोटे से जयंत चौधरी को राज्यसभा की सदस्यता भी मिल गयी थी।

लेकिन अब छोटे चौधरी के नाम से मशहूर जयंत चौधरी के पाला बदलने की अटकलों से विपक्षी खेमा बेचैन दिख रहा है। क्योंकि बात यह नहीं है कि छोटा दल गठबंधन से बाहर जा रहा है या बड़ा दल, बात यह है कि लंबे समय से गठबंधन में साथ रहा दल अब दूसरे के साथ जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ एक फोटो ट्वीट करते हुए ऐलान किया था कि रालोद के लिए गठबंधन में सात लोकसभा सीटें दी गयी हैं। लेकिन यह सात सीटें कौन-सी होंगी इसका ऐलान नहीं किया गया था। इस बात से जयंत चौधरी नाराज बताये जा रहे थे। जयंत चौधरी ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस से कुछ सीटें अपने लिये मांगी थीं लेकिन कांग्रेस की ओर से स्पष्ट इंकार कर दिये जाने के चलते उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इसलिए जब भाजपा की ओर से इस बार गठबंधन का प्रस्ताव आया तो उसे जयंत चौधरी मना नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि भाजपा के साथ जाने पर जयंत चौधरी को मथुरा, कैराना, अमरोहा और बागपत सीटें मिल सकती हैं। अभी इनमें से अमरोहा को छोड़कर बाकी तीनों सीटें भाजपा के पास हैं। बताया जा रहा है कि जयंत चौधरी भाजपा के प्रस्ताव को स्वीकार करने का मन बना चुके हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के क्षेत्रीय दल के दर्जे को बचाना है। यदि उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन लोकसभा चुनावों में मत हासिल नहीं किये तो संभव है कि उनका चुनाव चिह्न नल भी छिन जाये। जयंत चौधरी यह बात समझ रहे हैं कि भले समाजवादी पार्टी उन्हें लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दे दे लेकिन सीटें जीतने की ज्यादा संभावना भाजपा के साथ मिलकर लड़ने में ही है।

दूसरी ओर भाजपा भी यह समझ रही है कि किसान आंदोलन के दौरान से नाराज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट मतदाताओं को पूरी तरह तभी साधा जा सकता है जब राष्ट्रीय लोकदल साथ आ जाये। हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनावी नुकसान पश्चिमी क्षेत्र में ही हुआ था। 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप नहीं था इसलिए भाजपा 2024 में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। भाजपा का प्रयास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल की जाये और इसके लिए तमाम प्रयास किये भी जा रहे हैं। ऐसी भी चर्चा सामने आई कि जयंत चौधरी ने पांच से सात लोकसभा सीटों की मांग रखी थी लेकिन भाजपा की ओर से चार सीटों का ही वादा किया गया है। भाजपा को पता है कि यदि जयंत को ज्यादा सीटें दी गयीं तो उत्तर प्रदेश की अन्य सहयोगी पार्टियां अपना दल, सुभासपा और निषाद पार्टी भी ज्यादा सीटें मांगेंगी। बताया जा रहा है कि गठबंधन के बाद राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है और लोकसभा चुनावों के बाद केंद्र में भी एक पद मिल सकता है।

इस तरह की भी चर्चा है कि जयंत चौधरी की पार्टी 12 फरवरी से पहले भाजपा के साथ आ सकती है और जब 12 फरवरी को भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मुजफ्फरनगर पहुँचेंगे तो जयंत चौधरी भी साथ होंगे। हम आपको बता दें कि नड्डा लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर से पार्टी के एक महीने के ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता मोदी सरकार के जन-कल्याणकारी कदमों को रेखांकित करने के अलावा चुनाव घोषणापत्र के लिए किसानों और मजदूरों सहित ग्रामीण आबादी से सुझाव मांगेंगे। पार्टी के सदस्य लोगों से संवाद के दौरान गांवों में गायों और कृषि उपकरणों की पूजा भी करेंगे। देखा जाये तो नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मुजफ्फरनगर का चयन कर बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है क्योंकि यह क्षेत्र मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध का केंद्र था। हालांकि बाद में केंद्र ने उन कानूनों को वापस ले लिया था लेकिन आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है।

बहरहाल, जहां तक इंडी गठबंधन की बात है तो बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके कुछ और घटक या उन घटकों के बड़े नेता सत्तारुढ़ एनडीए का दामन थाम सकते हैं क्योंकि देश के राजनीतिक मिजाज से सभी वाकिफ हैं। सभी इस बात को समझ रहे हैं कि देश की ताजा राजनीतिक स्थिति यही है कि दस साल के शासन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम होने की बजाय देश-विदेश में और बढ़ी ही है।

आज का इतिहास

1968 ऑरेंजबर्ग, दक्षिण कैरोलिना में स्थानीय पुलिस ने भीड़ के लोगों को निकाल दिया, जो अलगाव का विरोध कर रहे थे, जिसमें तीन लोग मारे गए और सात अन्य घायल हो गए।

1971 दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नैस्डैक की शुरुआत हुई।

1978 अमेरिकी सीनेट की कार्यवाही को पहली बार रेडियो पर प्रसारित किया गया।

1979 जॉशिम योम्बी-ओपांगो के सत्ता से हटने के बाद डेनिस सासो न्गूस्सो को कांगो गणराज्य का नया राष्ट्रपति चुना गया।

1992 यूलिसिस अंतरिक्षयान बृहस्पति ग्रह के निकट से गुजरा।

1993 सुचोई की दुर्घटना में 134 निर्दोष यात्रियों की मौत - 24 टुपोलर यात्रियों की उड़ान में।

1994 जैक निकोलसन द्वारा एक कार पर हमला किया गया था और उन्होंने कार पर हमला करने के लिए एक गोल्फ क्लब का उपयोग किया था।

1995 ट्रूजिलो में 6.4 के पैमाने के साथ आए भूकंप में 46 निर्दोष लोग मारे गए थे।

1998 ओलंपिक इतिहास में पहली महिला आइस हॉकी खेल में फिनलैंड ने स्वीडन को लगभग 6-8 अंकों से हराया जो कि बहुत बड़ा नुकसान था।

2002 संयुक्त राज्य अमेरिका के साल्ट लेक सिटी यूटा में 19 वीं शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया।

2004 46 वें गामी पुरस्कार के प्रमुख पुरस्कार कोल्ड प्ले, आउट कास्ट, रिचर्ड मैन, लेदर वैंड्रॉस क्रिस्टीना एगुइलेना और जस्टिन टिम्बर लेक द्वारा जीते जाते हैं।

2008 उड़ीसा के शिशुपालगढ़ में खुदाई के दौरान 2500 वर्ष पुराना शहर मिला।

2010 द केनी स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए अमेरिकी अंतरिक्ष यान एंडेवर ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर दो सप्ताह के मिशन की सफलतापूर्वक शुरुआत कर दी है।

2011 उत्तर और दक्षिण करेन अधिकारियों ने कार्य स्तर की सैन्य वार्ता के लिए मुलाकात की और यह आठ महीनों में पहली कोरियाई वार्ता थी।

2012 लंदन में, क्रिस्टी में विन्सेंट वान गाग, केमिली पिसरो और एडगर डेगास द्वारा एलिजाबेथ टेलर की कलाकृतियों का संग्रह 13.7 मिलियन पाउंड से अधिक में बेचा गया था।

2013 इराक में बम विस्फोट में 29 लोगों की मारे गए और 69 घायल हुए।

राज्यसभा में मनोनयन पर हो चिंतन

प्रभु चावला

प्रारंभ में राज्यसभा में विशिष्ट लोगों को मनोनीत करने का उद्देश्य सदन के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना था। अब मनोनयन के माध्यम से विचारधारात्मक संदेश दिया जाता है तथा इसमें ग्लैमर, जाति और दलगत संबद्धता के भी आयाम होते हैं। बीते सात दशकों में मनोनीत सांसदों की भूमिका एवं गुणवत्ता में भारी बदलाव आया है। वे या तो अनुपस्थित रहते हैं या बहस से परे रह कर पीछे बैठे होते हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति ने निजी संस्थान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सतनाम सिंह को शिक्षा में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले सिंह बेहद सफल उद्यमी साबित हुए हैं। उनका चयन गरीब या सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले अनजान लोगों को चुनने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल को प्रतिबिंबित करता है। कांग्रेस के दौर में मनोनीत सांसद उसके वैचारिक सहयोगी हुआ करते थे। अब जो लोग मनोनीत हो रहे हैं, वे राजनीतिक रूप से तटस्थ हैं और दिखाई नहीं देते। वर्ष 1952 में राज्यसभा की स्थापना के बाद से लगभग 145 लोग मनोनीत हुए हैं, इनमें से कुछ का चयन एक बार से अधिक हुआ है। इनमें सबसे अधिक संख्या (24) मनोरंजन जगत से आने वालों की है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने 65, राजीव गांधी ने 12 तथा मनमोहन सिंह ने 19 लोगों को मनोनीत किया था। सभी 14 प्रधानमंत्रियों के लिए केवल मेधा ही मानक नहीं रही है, लेकिन मनोनयन प्रक्रिया का प्रारंभ कृपादृष्टि के सर्कस के रूप में नहीं हुआ था। नेहरू ने विभिन्न क्षेत्रों के सबसे उत्कृष्ट लोगों को मनोनीत किया था। पहले 12 सदस्यों में जाकिर हुसैन (शिक्षाविद), अल्लादी कृष्णास्वामी (कानून विशेषज्ञ), सत्येंद्र नाथ बोस (वैज्ञानिक), रुक्मिणी देवी अरुंडेल (कलाकार), काकासाहेब कालेलकर (विद्वान), मैथिलीशरण गुप्त (कवि) एवं पृथ्वीराज कपूर (कलाकार) शामिल थे। भारतीय सिनेमा के बहुत बड़े नाम पृथ्वीराज कपूर ने अपने पहले भाषण में कहा था, 'हम भले आकाश में उड़ते हों, पर धरती से हमारा जुड़ाव कभी नहीं टूटना चाहिए, पर यदि हम बहुत अर्थशास्त्र और राजनीति पढ़ने लगते हैं, तब हमारा यह जुड़ाव गायब होने लगता है, हमारी आत्मा सूखने लगती है। आत्मा के इस सूखने से हमारे नेताओं को बचाना होगा। इसी उद्देश्य के लिए मनोनीत सदस्य- शिक्षाविद, वैज्ञानिक, कवि, लेखक और कलाकार- यहां हैं।'

हालांकि नेहरू ने यह सुनिश्चित किया था कि पहली टीम वाम उदारवाद और अंतरराष्ट्रीयतावाद से वैचारिक रूप से जुड़ी हुई हो। बाद के उनके चुनाव भी बहुत उत्कृष्ट थे- तारा चंद (इतिहासकार), जयरामदास दौलतराम, मोहन लाल सक्सेना एवं आरआर दिवाकर (सामाजिक कार्यकर्ता)। नेहरू शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को पसंद करते थे और इंदिरा ने भी यही राह अपनायी, पर वे वैसे लोगों को तरजीह देती थीं, जो उनके प्रति निष्ठावान भी हों और उनके राजनीतिक दर्शन को भी आगे बढ़ाएं, जैसे कवि हरिवंश राय बच्चन, वामपंथी इतिहासकार नुरूल हसन, उदारवादी शिक्षाविद रशीदुद्दीन खान व वीपी दत्त और कलाकार हबीब तनवीर। राजीव गांधी ने सलीम अली (पक्षी विज्ञानी), अमृता प्रीतम (साहित्यकार), इला भट्ट (सामाजिक कार्यकर्ता), एमएफ हुसैन (कलाकार), आरके नारायण (साहित्यकार) और रवि शंकर (संगीतज्ञ) को मनोनीत किया था। नरसिम्हा राव वैजयंती माला समेत केवल चार मनोनयन कर सके। इससे आइके गुजराल को लाभ हुआ, जिन्होंने एक ही दिन में आठ लोगों को मनोनीत किया, जिनमें शबाना आजमी भी थीं।

वाजपेयी ने भी हर क्षेत्र के सिलेब्रिटी लोगों के मनोनयन के सिद्धांत का अनुकरण किया, पर साथ ही जाति या क्षेत्र के आधार पर असफल या सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े नेताओं को भी मनोनीत किया। साल 1998 से 2003 के बीच मनोनीत 11 सदस्यों में तीन- लता मंगेशकर, दारा सिंह और हेमा मालिनी- बॉलीवुड से थे। वाजपेयी ने तीन वैज्ञानिकों, राजनीतिक लाभ के लिए अर्थशास्त्री बिमल जालान, प्रख्यात न्यायविद फाली नरीमन तथा तीन नेताओं को चुना। इनमें से कुछ ने बहसों में बड़ा योगदान दिया, पर विधायिका के जटिल काम से लगभग अलग ही रहे। मनमोहन सिंह ने भी नाम और प्रसिद्धि के आधार पर चयन किया। उनकी सरकार ने लगभग 15 लोगों को मनोनीत किया, जिनमें तीन फिल्म जगत से थे- जावेद अख्तर, श्याम बेनेगल और रेखा। रेखा का चयन एक रहस्य है, क्योंकि उन्होंने किसी भी विषय पर शायद ही कभी एक पंक्ति बोला हो। मनमोहन के अन्य चयन में दो मीडिया पेशेवर, दो कॉर्पोरेट नेता- अशोक गांगुली और अनु आगा, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन और अर्थशास्त्री सी रंगराजन। दबाव में उन्होंने गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान कपिला वात्स्यायन और मणि शंकर अय्यर को भी जगह दी। मशहूर वकील राम जेठमलानी को लालू प्रसाद के दबाव के कारण मनोनीत करना पड़ा था।

अपने पहले कार्यकाल में मोदी ने पार्टी एवं बाहर के विभिन्न समूहों व व्यक्तियों के प्रायोजित लोगों को मनोनीत किया, पर बाद में वे निष्ठा और उपयोगिता को देखने लगे। अभी तक उन्होंने लगभग 20 मनोनयन किया है। उनकी सिलेब्रिटी पसंद के वैचारिक और राजनीतिक आयाम हैं- पश्चिम बंगाल से रूपा गांगुली, केरल से सुरेश गोपी एवं पीटी उषा, तमिलनाडु से इलैयाराजा और पूर्वोत्तर से मेरी कॉम। मोदी ने राजनीतिक शोर को अनदेखा कर पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को मनोनीत किया। अभी तक इनकी बहस की प्रतिभा नहीं देखी गयी है। इलैयाराजा शायद ही कभी दिखते हैं। गोगोई की उपस्थिति 40 प्रतिशत है। पहले सिलेब्रिटी लोगों के प्रभाव का उपयोग नेहरूवादी और कांग्रेसी विचार को बढ़ाने के लिए होता है, पर वर्तमान में वे मिशन मोदी को बढ़ावा देने में विफल रहे हैं। उन्हें चुनाव में लड़ा कर ही मंत्री बनाया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनोनीत सदस्यों में से अधिकतर ने देश का गौरव बढ़ाया है। अशोक विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि बीते 12 वर्षों में मनोनीत सदस्य ज्यादातर अनुपस्थित रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति 22 और दारा सिंह की 57 प्रतिशत रही थी। अधिकतर सदस्यों ने विकास कार्यों के लिए आवंटित धन को भी खर्च नहीं किया। समय आ गया है कि मनोनयन की अवधारणा की समीक्षा हो।

बदलने आये थे राजनीति, केजरीवाल ने खुद को पूरी तरह बदल डाला

नीरज कुमार दुबे

देश की राजनीति बदलने के नाम पर राजनीति में आये अरविंद केजरीवाल राजनीति को बदलने की बजाय खुद ही बदल गये। वादा किया था बंगला नहीं लूंगा मगर शीश महल बनवा लिया, वादा किया था कि सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा मगर अब बड़ी-बड़ी गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं, कहते थे कि सुरक्षा नहीं लूंगा लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक आज दिल्ली और पंजाब पुलिस के जवानों की फौज उनकी सुरक्षा में तैनात है। ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं जो साबित करते हैं कि अन्ना आंदोलन के दौरान वाले केजरीवाल और अब सत्ता का स्वाद चख चुके केजरीवाल में कितना परिवर्तन आ चुका है। पहले केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया करते थे, बड़े-बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा कर तमाम तरह के दस्तावेज पेश किया करते थे मगर आज खुद केजरीवाल और उनकी सरकार तथा पार्टी के तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में हैं। यही नहीं, जिन लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार को वह बड़ा मुद्दा बनाया करते थे आज उनके साथ मंच साझा करने या उनके खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई का विरोध करने से वह गुरेज नहीं करते। केजरीवाल हर बात में संविधान का हवाला जरूर देते हैं लेकिन अपने आचरण से वह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री संविधान में लिखी बातों का पालन कर रहे हैं? हाल ही में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है और कुछ विधायकों की खरीद-फरोख्त का प्रयास किया गया है। ऐसा ही आरोप कुछ समय पहले भी केजरीवाल ने लगाया था मगर कोई सबूत नहीं पेश किया था। अब केजरीवाल ने अपना आरोप दोहराते हुए फिर कोई सबूत नहीं पेश किया है। आश्चर्य है कि सेना से उसके शौर्य का सबूत मांगने वाले केजरीवाल खुद कोई सबूत देने से बचते हैं। सबूत देना तो क्या वह तो जांच में शामिल होने से भी बचते हैं। आंदोलन के दौरान केजरीवाल कहते थे कि आम जनता और वीआईपी पर सभी नियम समान होने चाहिए लेकिन वीआईपी बनते ही वह खुद को नियमों से परे समझने लग गये हैं। ईडी ने शराब घोटाला मामले में उन्हें पांच समन भेजे मगर वह पेश नहीं हुए और उल्टा ईडी पर ही आरोप लगा दिया कि उन्हें भेजे गये समन कानूनी रूप से गलत हैं। सवाल उठता है कि यदि ईडी बार-बार केजरीवाल को गलत समन भेज रही है तो वह इस संबंध में शिकायत क्यों नहीं दर्ज करा रहे या अदालत क्यों नहीं जा रहे? यही नहीं, जब केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है तो जाहिर है कि इस गंभीर आरोप की जांच होनी चाहिए। यदि सरकार गिराने का कोई प्रयास हुआ है तो दोषी को न्याय के कठघरे में लाया ही जाना चाहिए। केजरीवाल की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह सरकार गिराने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने में मदद करें लेकिन वह तो दूर भाग रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनके आरोपों के संबंध में उन्हें नोटिस देना चाहती है ताकि इस मामले का सच सामने आ सके लेकिन केजरीवाल और उनकी मंत्री नोटिस स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री द्वारा लगाये गये आरोप झूठे थे? सवाल उठता है कि यदि आरोप झूठे थे तो क्या केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल उठता है कि क्या राजनेताओं को झूठे आरोप लगा कर अपनी राजनीति चमकाने और जनता के बीच भ्रम फैलाने की इजाजत देनी चाहिए? बहरहाल, भाजपा ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होंगे। पार्टी की दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा है कि करप्शन किंग केजरीवाल कितना भी भाग लें लेकिन उनकी चोरी और पापों का हिसाब होकर रहेगा। उन्होंने कहा है कि जहां चोर गैंग के बाकि साथी हैं वहीं उनका गैंग लीडर भी जाएगा।

भाजपा की गुगली पर चंपई सोरेन का छक्का

अभिरंजन कुमार

झारखंड में खेला होने के कयासों के विपरीत चंपई सोरेन सरकार ने विधानसभा में आसानी से अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह पर मुख्यमंत्री बनाए गए चंपई सोरेन ने 81 सदस्यों की विधानसभा में 47 सदस्यों के समर्थन का दावा किया था, जो कि बिल्कुल सही निकला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 और कांग्रेस के 17 विधायक तो एकजुट रहे ही, राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक भी विपक्षी गठबंधन के साथ ही रहा। इस राजनीतिक घटनाक्रम को बीजेपी की गुगली पर विपक्ष के छक्के के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कि विपक्षी गठबंधन को कम से कम छह बड़े फायदे होते दिखाई दे रहे हैं। चंपई सोरेन सरकार ने जिस आसानी से सदन में अपना बहुमत साबित किया है, उससे लगता है कि अब कम से कम लोकसभा चुनाव तक तो उसे कोई खतरा नहीं है। झारखंड में विधानसभा के चुनाव भी इसी साल के अंत में होने वाले हैं। ऐसे में यदि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहता है, तो उसमें टूट-फूट आसान नहीं होगी और संभव है कि विधानसभा के चुनाव में भी विपक्षी खेमा ऊंचे मनोबल के साथ उतरे। कथित ज़मीन घोटाले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने विपक्षी कैम्प के लिए एक अलार्म जैसा काम किया। उन्हें लगा कि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर विपक्ष का कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। चाहे इसे एक किस्म का डर कहें या बचाव की तैयारी, इसने विपक्षी खेमे में चट्टान जैसी एकजुटता ला दी। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों मुख्य विपक्षी पार्टियों ने अपने-अपने विधायकों को संभालकर रखने के लिए अतिरिक्त सतर्कता दिखाई, वहीं इन दोनों पार्टियों ने अपना तालमेल भी बढ़ाया है। कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूर्ण नैतिक समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने भी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात करके उन्हें अपने पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज भाजपा नेता विपक्षी पार्टियों में व्याप्त परिवारवाद पर तीखा हमला करते रहे हैं, लेकिन चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने से हेमंत सोरेन पर अब परिवारवाद का आरोप चस्पा करना आसान नहीं होगा। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह संदेश दे दिया है कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि शिबू सोरेन परिवार के किसी सदस्य को ही आगे किया जाए, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में मुख्यमंत्री की कुर्सी और सत्ता के बंटवारे को लेकर हेमंत सोरेन परिवार में कलह की बात भी कही जा रही थी। खास कर जबसे ऐसी ख़बरें सामने आईं कि गिरफ्तारी की स्थिति में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, तब से उनकी भाभी सीता सोरेन की नाराज़गी बहुत छिपी हुई नहीं रह पाई थी। लेकिन अंत में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर हेमंत ने जैसे सब कुछ संभाल लिया। चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत के दौरान हेमंत सोरेन ने सदन में भावुकता भरा भाषण दिया। एक तरफ जहां उन्होंने सदन में चुनौती दी कि जिस साढ़े आठ एकड़ ज़मीन के कथित घोटाले को लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अगर उसकी मिल्कियत उनके नाम से साबित कर दी जाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे, वहीं उन्होंने अपने खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई को संपूर्ण आदिवासी समाज के खिलाफ अत्याचार से भी जोड़ने की कोशिश की।

नीतीश के असल परिणाम अभी आना बाकी हैं

उमेश चतुर्वेदी

भारतीय गांवों का एक खेल है, दोल्हा-पाती। इसमें खिलाड़ी अपने को बचाने के लिए लगातार एक डाल से दूसरी डाल पर फांदते-कूदते रहते हैं। इस तरह वे खुद को खेल के नियम के अनुसार बचाने की कोशिश करते रहते हैं। वैसे तो यह खेल भारत के तकरीबन हर इलाके के गांवों में प्रचलित है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में यह खेल कुछ ज्यादा ही प्रचलित रहा है। शायद यही वजह है कि बिहार की नौंवी बार कमान संभाल चुके नीतीश कुमार को लेकर दोल्हा-पाती के खिलाड़ी जैसी अवधारणा बन गई है। करीब एक दशक में जिस तरह चार बार नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला, अपने साथी बदले, वह कूद-फांद का ही रूप है।

दिलचस्प है कि नैतिकता और मर्यादा की सबसे ज्यादा दुहाई राजनीति देती है, लेकिन नैतिकताओं और मर्यादाओं का भंजन सबसे ज्यादा राजनीति ही करती है। नीतीश, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, कम से कम बिहार के संदर्भ में तीनों ही इसी प्रवृत्ति के उदाहरण बनकर सामने आए हैं। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था, नीतीश कुमार ने उन्हें सांप्रदायिक करार देते हुए उस आठ साल से जिस पार्टी के साथ सत्ता चला रहे थे, उस भाजपा का दामन छोड़ दिया था। इसके पहले भी वे नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी सोच को जाहिर कर चुके थे। साल 2008 में जब कोसी नदी ने समंदर का रूप धर लिया था, तब गुजरात से बिहार पहुंची राहत की खेप को नीतीश ने बैरंग वापस करा दिया था। क्योंकि उस वक्त उनकी नजर में सांप्रदायिक नरेंद्र मोदी गुजरात के

मुख्यमंत्री थे।

2013 में नीतीश कुमार ने उस लालू का दामन थाम लिया, जिनके विरोध में उन्होंने 1994 में जनता दल छोड़कर जार्ज फर्नांडिस की अगुआई में समता पार्टी बनाई थी। भाजपा के साथ 1996 में समता पार्टी ने जो गठबंधन किया, उसका नतीजा ही रहा कि 2005 के बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश की अगुआई में लालू यादव की लगभग अजेय समझी जाने वाली सत्ता को उखाड़ फेंका गया। तब नीतीश ने नया इतिहास रचा, लेकिन इसमें सहयोग बीजेपी का भी रहा। नीतीश-भाजपा की सरकार ने 2006-2010 के दौरान बिहार की कार्यशैली बदली, कानून-व्यवस्था को बेहतर किया और कई कीर्तिमान रचे। इसका असर यह हुआ कि 2010 के विधानसभा चुनावों में लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल की चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी पराजय हुई। ऐसा माना जाने लगा कि लालू यादव की पार्टी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने 2013 में पलटी मारी और इसके बाद 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल को जैसे जीवनदान मिल गया। लेकिन नीतीश को लालू का यह साथ ज्यादा दिन रास नहीं आया। हालांकि इस बीच बिहार के जीन को लेकर नीतीश कुमार ने ऐसा अभियान चलाया कि बोरे में भरकर बिहार के लोग अपने बाल नरेंद्र मोदी के पते पर भेजते रहे। तब बिहारी लोगों का बाल उनकी शुद्ध बिहारी जीन का प्रतीक था।

लालू बेशक नीतीश के सहयोगी बने, लेकिन वे 1994 की दगाबाजी नहीं भूले। धीरे-धीरे शासन में लालू परिवार का दबदबा बढ़ा तो नीतीश ने 2017 में फिर बीजेपी का साथ ले लिया। इसका उन्हें 2019 के आम चुनावों में फायदा भी हुआ। उनके 16 सांसद चुने गए। बीजेपी को अपनी पुराने 22 सांसदों में से कुछ के टिकट काट कर उनकी सीट जनता दल यू को देनी पड़ी। इसी गठबंधन ने 2020 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा। इस चुनाव में लोकजनशक्ति-रामविलास गुट के नेता चिराग ने सिर्फ जनता दल यू की सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे और 2005 के बाद पहली बार नीतीश की पार्टी को सबसे कम यानी 5 सीटें मिलीं। नीतीश ने इसे बीजेपी का खेल माना और 10 अगस्त 2022 को बीजेपी का साथ छोड़ उस आरजेडी का दामन थाम लिया, जिसके नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें पलटू चाचा की उपाधि दी थी। बिहार में 28 जनवरी 2024 को नीतीश ने फिर पाला बदल लिया और उनके लिए सारे दरवाजे बंद करने का बार-बार दावा करने वाली बीजेपी ने बदले हालात में उनके लिए दरवाजे खोल दिए। नीतीश भी अपना वह बयान भूल गए कि मर जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार की छवि पलटू बाबा के रूप में स्थायी हो गई।

राजनीति दरअसल समूचा शीर्ष नेतृत्व का खेल है। दिलचस्प यह है कि शीर्ष नेतृत्व सारे कदम अपने कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भावनाओं के नाम पर उठाती है। जब भी कोई गठबंधन टूटता है तो घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता पुराने साथी को दुश्मन मानकर उसके खिलाफ दुश्मनी की हद तक हमलावर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर वही दल साथ आ जाते हैं तो जमीनी स्तर पर दुश्मनी निभाने वालों के सामने खीस निपोरने और ठगा महसूस करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। बिहार में भी यही हो रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं सूझ रहा कि वे अब उस नीतीश को कैसे पचाएं, जिन्होंने उन्हें अछूत बताया, उनके नेताओं को विधानसभा में खरी-खोटी सुनाई। विधानसभा अध्यक्ष का आसन सदन में सबसे ऊंचा होता है।

लेकिन नीतीश ने उस आसन पर बैठे विजय सिन्हा को भी नहीं छोड़ा था। सदन में महिलाओं को लेकर उन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले तकरीबन अश्लीलता की हद तक का बयान दिया था। तब भाजपा की एक विधायक फूट-फूटकर रो पड़ी थीं। बदले हालात में उनकी स्थिति का अनुमान ही लगाया जा सकता है। जनता दल यू के एक वरिष्ठ नेता ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि उनका अपना कोर वोटर, जिसमें नीतीश की अपनी कुर्मी जाति के भी लोग हैं, अब गाली देने लगे हैं। उनके सामने भी नीतीश की लानत-मलामत की गई। लोगों का कहना है कि क्या बिहार के राजनीतिक दलों और नेताओं की आंखों में पानी नहीं रह गया है? बिहार के बदले राजनीतिक गठबंधन की नई सरकार को बिहार के हित में बताया जा रहा है। इससे बीजेपी खुद को बेहतर स्थिति में पा रही है। राष्ट्रीय जनता दल खुद को ठगा महसूस कर रहा है।

क्या काशी दोहरा रही है अयोध्या का इतिहास?

संजय तिवारी

काशी में ज्ञानवापी आने से पहले अयोध्या की राम जन्मभूमि चलते हैं। वह साल था 1986। फैजाबाद जिला अदालत में एक याचिका आयी जिसमें निवेदन किया गया था कि रामलला जन्मस्थान पर हिन्दुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए और वहां लगा ताला खोल दिया जाए। उस समय जो जज थे उन्होंने इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि वहां रामजन्मभूमि परिसर में ताला लगाने का तो कोई वैधानिक या प्रशासनिक आदेश ही नहीं है। फिर वहां ताला लगा क्यों है? 1949 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जीबी पंत के मौखिक आदेश पर ताला लगाया गया था लेकिन लिखित आदेश की कोई प्रति जिला प्रशासन के पास मौजूद नहीं थी। जिला जज केएम पांडेय ने आदेश दिया कि जब ताला लगाने का कोई आदेश ही नहीं है तो वहां ताला लगाकर रखने का औचित्य क्या है? इसके बाद अयोध्या के मस्जिद ए जन्मस्थान में रामलला विराजमान का ताला खोल दिया गया।

अब कुछ ऐसी ही घटना काशी में घटित हुई है। 1992 में जब रामलला जन्मस्थान को कारसेवकों ने अतिक्रमण से मुक्त करवा लिया तब उस समय उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश में जहां इन मुद्दों से बीजेपी का हिन्दू वोट बैंक मजबूत हो रहा था, वहीं मुलायम सिंह यादव मुस्लिम वोटबैंक मजबूत करने में जुटे थे। अयोध्या में गोलीकांड करनेवाले मुलायम ने काशी के ज्ञानवापी में भी हिन्दुओं के प्रवेश पर तालाबंदी करवा दी। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर को तोड़कर बनी मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गयी और उस सुरक्षा घेरे के अंदर हिन्दुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी।

उस समय तक हिन्दू समुदाय उस परिसर में मां श्रृंगार गौरी का पूजन करता था जो पुराने मंदिर के अवशेष पर खड़ी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर है। क्योंकि वह मंदिर की वही पुरानी दीवार है जिसे तोड़कर उस पर तीन गुंबद वाली मस्जिद बनायी गयी थी इसलिए श्रद्धालु वहां मां श्रृंगारगौरी का पूजन करते आ रहे थे। मुस्लिमों ने भी कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। इसी के साथ ज्ञानवापी परिसर में ही स्थित तीन तहखानों में दो मुस्लिम पक्ष के पास थे और एक काशी के व्यास परिवार के पास था। इसे व्यासजी का तहखाना कहा जाता था जहां उनका परिवार नियमित पूजा पाठ करता था। 1993 से पहले तक यह सब सुचारु रूप से हो रहा था और दोनों पक्ष लगभग एक दूसरे के हक को स्वीकार कर चुके थे। व्यास जी के तहखाने में तो देशी विदेशी पर्यटक भी आते जाते थे। लेकिन 1993 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने श्रृंगार गौरी के पूजन को वर्ष में एक बार सीमित कर दिया और व्यास जी के तहखाने पर ताला मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया। हाल ही में 31 जनवरी को वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुनाया तो ठीक वही बात बोली जो 1986 में अयोध्या मामले में वहां के जिला जज केएम पांडेय ने कही थी। जज अजय विश्वेश ने पाया कि 1993 में व्यासजी के तहखाने को बंद करने का कभी कोई लिखित आदेश ही पारित नहीं हुआ था फिर उस पर ताला लगाकर रखने का क्या औचित्य है? इसलिए ब्रिटिश काल से कानूनी रूप से उस तहखाने के अधिकारी व्यास परिवार को जज ने वहां फिर से पूजा पाठ करने का अधिकार दे दिया। जिला प्रशासन ने उसी रात सारी व्यवस्था करके व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरु भी करवा दिया।

इन दोनों ही घटनाओं को देखें तो यह बात समान रूप से नजर आती है कि दोनों ही स्थानों पर एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए गैर कानूनी तरीके से हिन्दुओं के अधिकार को सीमित किया गया। इसके लिए कोई लिखित प्रशासनिक आदेश देने की बजाय सत्ता के बल पर मौखिक आदेश से मुख्यमंत्रियों ने जो चाहा वो किया। फिर वो अयोध्या के मामले में जीबी पंत हों या फिर काशी के मामले में मुलायम सिंह यादव। इसलिए जब इन प्रतिबंधों की वैधानिक जांच की गयी तो पता चला कि ऐसा तो कोई लिखित आदेश ही नहीं है तो फिर ताला लगाकर रखने का क्या औचित्य रह जाता है? इसे संयोग कहें या शायद दैवीय विधान कि काशी की ज्ञानवापी अयोध्या के रामजन्मभूमि मंदिर का इतिहास दोहराते हुए नजर आ रही है। जिस तरह जिला अदालत के दखल के बाद वहां ताला खुला था उसी तरह ज्ञानवापी में भी जिला अदालत के आदेश के बाद व्यासजी के तहखाने का ताला खुल गया है। जिस तरह अदालत के आदेश के दो घण्टे बाद ही ताला खोलकर रामलला का पूजा पाठ शुरु हो गया था उसी तरह वाराणसी जिला अदालत के आदेश वाली रात ही ज्ञानवापी परिसर में गैरकानूनी तरीके से बंद की गयी पूजा शुरु हो गयी।

दिसंबर 1993 तक व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ पर मुस्लिम समुदाय को भी कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ असामाजिक तत्व परेशान जरूर करते थे लेकिन ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजा पाठ कभी बंद नहीं हुआ। अब क्योंकि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद ही ज्ञानवापी का फैसला आया इसलिए मुस्लिम समुदाय इस पर भी आपत्ति दिखा रहा है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने तत्काल न सिर्फ भड़कानेवाली बयानबाजी शुरु कर दी बल्कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्सासजी के तहखाने में फिर से शुरु हुई पूजा पाठ को रोकने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट में भले ही अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को हो लेकिन शुक्रवार को ही देश के अधिकांश मस्जिदों से भड़कानेवाले बयान जारी किये गये। शुक्रवार को मौलाना जो जुमे का खुतबा देते हैं उसमें उन्होंने कहीं खुलकर तो कहीं इशारों इशारों में इस अदालती आदेश को अपने साथ अन्याय बताया और %अपना समय आने पर सबकुछ ठीक कर लेने% की धमकियां भी दी।

ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने को लेकर स्थानीय जिला अदालत ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया है जो वहां पहले से नहीं हो रहा था। अदालत ने इसे व्यास परिवार का अधिकार मानते हुए तहखाने में उनके पूजा के अधिकार को लौटा दिया है। लेकिन इसे भी मुस्लिम मौलाना अपने समुदाय में इस तरह फैला रहे हैं जैसे मुसलमानों के अधिकार को छीन लिया गया है और मुसलमानों को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है। यह एक गैरजिम्मेदार और न्याय विरुद्ध रवैया है, यदि मुस्लिम उलेमा, मौलाना इसका त्याग कर देंगे तो दोनों पक्षों को सच जानने और समझने का मौका मिलेगा। मुस्लिम समुदाय में फैलायी गयी हर झूठी और उकसावे वाली जानकारी केवल मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिन्दुओं को भी उत्तेजित करेगी। इससे समाज में अस्थिरता और अशांति फैलेगी जो हिन्दू-मुस्लिम ही नहीं पूरे देश के माहौल के लिए अच्छा नहीं होगा।

यूपीएससी क्रैक करने के बाद सीखनी पड़ती है नई भाषा

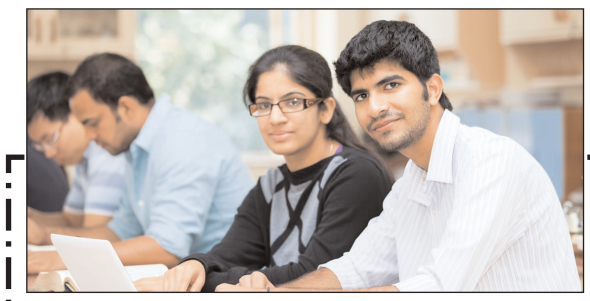

इस योजना के तहत भारतीय छात्रों को मिलेगा यूनाइटेड किंगडम जाने का मौका

देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु के नाम से कई स्कॉलरशिप चलाई जाती हैं। इन स्कॉलरशिप का लक्ष्य मेधावी छात्र-छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन्हीं में नेहरू ट्रस्ट यूके ट्रैवल अवार्ड्स है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, दीर्घाओं, या संरक्षण, अध्ययन से संबंधित अन्य निर्दिष्ट संस्थानों में काम करने वाले छात्र-छात्राओं या पेशेवर के लिए विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में भारतीय संग्रह के लिए नेहरू ट्रस्ट द्वारा पेश किया गया एक अवसर है।

जानिए क्या है यह योजना

जिसमें भाग लेकर भारत की कला और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करना शामिल है। आपको बता दें कि इस इंटर्नशिप के तहत दो उम्मीदवारों को शोध, अध्ययन, सम्मेलनों में उपस्थिति और सहकर्मियों के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए छोटी अवधि के लिए यूनाइटेड किंगडम जाने का मौका मिलेगा। इस इंटर्नशिप के लिए चयनित उम्मीदवार को भारत से जाने और रहने आदि अन्य खर्चों के लिए आंशिक लागत योगदान के रूप में अधिकतम 1,000 प्रदान किए जाएंगे।

बता दें कि विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में भारतीय संग्रह के लिए नेहरू ट्रस्ट का गठन किया गया है। इसके तहत कला और सांस्कृतिक विरासत के अध्ययन, उसके संरक्षण और प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया जाना इसका उद्देश्य है। वहीं इच्छुक उम्मीदवार 15 फरवरी 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्वालिफिकेशन

भारतीय नागरिक होना चाहिए

भारत की कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, अध्ययन से संबंधित विश्वविद्यालयों, संग्रहालयों, दीर्घाओं और अन्य निर्दिष्ट संस्थानों में काम करने वाला पेशेवर या विद्वान होना चाहिए।

फायदा

इस योजना के लिए चयनित उम्मीदवार को आंशिक लागत योगदान के रूप में अधिकतम 1,000 प्रदान किए जाएंगे।

डॉक्यूमेंट्स

प्रोफार्मा, आवेदन फार्म,

उद्देश्य का विवरण

व्यावसायिक और शैक्षणिक रुचियों और अनुभव का विवरण

व्यावसायिक या कैरियर योजनाओं के लिए परियोजना की प्रासंगिकता।

रेलवे ने सहायक लोको पायलट के 5696 पदों पर निकाली भर्ती, 20 जनवरी से शुरू हुए आवेदन

अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि हाल ही में रेलवे भर्ती बोर्ड ने विभिन्न रेलवे रीजन में सहायक लोको पायलट के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत 5696 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

ऐसे में आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार विभिन्न जोन की रीजनल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बताए गए स्टेप्स के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

उम्र

आरआरबी सहायक लोको पायलट भर्ती अधिसूचना के अनुसार, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल और ओबीसी अभ्यर्थियों को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के पूर्व कर्मचारियों को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। वहीं ओबीसी एनसीएल श्रेणी के अभ्यर्थियों को 6 साल और एससी और एसटी श्रेणियों को 8 साल की छूट मिली है।

इसके साथ ही सामान्य, ओबीसी और एससी-एसटी कैटेगिरी की विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को 3,5 और 10 साल तक की छूट दी जाएगी। वहीं विभिन्न पदों पर कार्यरत रेलवे कर्मचारियों को भी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं।

क्वालिफिकेशन

सहायक लोको पायलट पद के लिए अभ्यर्थी की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिटर, मिलराइट/रखरखाव मैकेनिक, मैकेनिक (मोटर वाहन), वायरमैन, मैकेनिक (रेडियो और टीवी), इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक जैसे विभिन्न ट्रेडों में एनसीवीटी/एससीवीटी के मान्यता प्राप्त संस्थानों से मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी के साथ आईटीआई होना चाहिए। वहीं अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं।

लास्ट डेट

इस भर्ती के लिए 20 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। ऐसे में आवेदन के इच्छुक रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन के स्टेप्स के बारे में बताया गया है। वहीं 19 फरवरी के बाद किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।

जानें कैसी होती है LBSNAA में IAS Training

यूपीएससी परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा कही जाती है. इसे क्रैक करने में कई उम्मीदवारों को सालों लग जाते हैं. इस परीक्षा को क्रैक करने वाले सिविल सर्वेंट के कंधों पर अहम जिम्मेदारी होती है. यही वजह है कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद भी कैंडिडेट्स को सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है. मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में IAS की ट्रैनिंग होती है. यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक करने वाले कैंडिडेट्स IAS, IPS, IFS और IRS Officer जैसे पदों पर सेलेक्ट होते हैं. एक आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसी होती है? इसमें क्या-क्या करना होता है? इन सभी सवालों के जवाब यहां देख सकते हैं.

कहां होती है IAS Training?

यूपीएससी परीक्षा क्रैक करने वाले उम्मीदवारों को मसूरी के लाल बहादूर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जाना होता है. यहां कैंडिडेट्स को बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाए जाते हैं. यहां आने वाले सभी कैंडिडेट्स अपने प्रोफाइल पर यहां की यादें जरूर साझा करते हैं. सिविल सर्विस परीक्षा क्रैक करने के बाद सभी की एक समान ट्रेनिंग यहां होती है.

IAS Officer की ट्रेनिंग कैसी होती है?

LBSNAA में ट्रेनिंग के लिए आने वाले कैंडिडेट्स को फिजिकल फिटनेस से लेकर मेंटल हेल्थ मजबूत कराया जाता है. यहां ट्रेनिंग के दौरान हिमालय ट्रैक्रिंग भी कराई जाती है. हर ट्रेनी को इसमें शामिल होना होता है. इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है. यहां सभी को ऑफिसर रैंक मिलने से पहले सभी क्षेत्र में सक्षम बनाया जाता है.

सीखनी पड़ती है नई भाषा

यूपीएससी सिविल सर्विस फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू राउंड से मिलने वाले मार्क्स के आधार पर रैंक मिलता है. इन्हीं रैंक के हिसाब से उन्हें, IAS, IPS या IFS के लिए सेलेक्ट किया जाता है. रैंक के अनुसार, ही कैंडिडेट्स को कैडर अलॉट होता है.

मसूरी के LBSNAA में ट्रेनिंग होने के बाद ऑफिसर्स को उनके कैडर स्टेट में भेजा जाता है. ऐसे में स्टेट में सही से काम कर सकें इसके लिए सभी ट्रेनी को स्थानिय भाषा भी सीखनी पड़ती है. भाषा की जानकारी होने के बाद कैंडिडेट्स को फिर मसूरी आना होता है और लास्ट में उन्हें ज्वॉइनिंग मिलती है.

अब ना चलें भेड़चाल, 12वीं के बाद चुनें ये टॉप ऑफबीट करियर, होगी लाखों में कमाई

कक्षा 12वीं में तीन स्ट्रीम- कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस की पढ़ाई होती है. साइंस में बायोलॉजी या मैथ्य में से कोई एक लेना होता है. आमतौर पर कॉमर्स लेने वाले छात्र 12वीं के बाद सीए, बैंकिंग या बीकॉम करते हैं. वहीं, साइंस बायोलॉजी वालें छात्र मेडिकल या फार्मेसी में जाते हैं. जबकि साइंस वाले इंजीनियरिंग को चुनते हैं. बहुत कम छात्र इस लीक से हटकर करियर बनाने की सोचते हैं.

आर्ट्स स्ट्रीम वालों के पास करियर विकल्प के तौर पर कई ऑप्शन होते हैं, फिर भी भेड़चाल करते हुए सिविल सर्विस की तैयारी या ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग को चुनते हैं. इस आर्टिकल में आप कम समय में ज्यादा कमाई कराने वाले कोर्स के बारे में देख सकते हैं. इन कोर्स को करने के बाद आप लाखों की नौकरी पा सकते हैं.

करें ये ऑफबीट कोर्स

क्रिएटिव मीडिया- 12वीं के बाद छात्र क्रिएटिव मीडिया में कोर्स करके शानदार नौकरी पा सकते हैं. इन दिनों क्रिएटिव आर्ट काफी डिमांड में है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हद्धस्न्ञ्ज से टेक्सटाइल डिजाइनिंग और लेदर डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं. अगर आप क्रिएटिव स्किल रखते हैं तो गेम डिजाइनर कोर्स भी कर सकते हैं. कई कंपनियां हाई सैलरी पर इन्हें हायर करती हैं.

ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स- मार्केट में ग्राफिक डिजाइनिंग के क्षेत्र में कई तरह के कोर्स मौजूद हैं. 12वीं के बाद शॉर्ट टर्म कोर्स के तौर पर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं. इसमें फाइन बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिजाइन, विजुअल कम्यूनिकेशन प्रोग्राम, प्रींटिंग एंड मीडिया इंजीनियरिंग कोर्स और विजुअल कम्यूनिकेशन जैसे कोर्स काफी मशहूर हैं.

पेंट टेक्नोलॉजी कोर्स- ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और होम फर्निशिंग कंपनियां पेंट टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट को हाई सैलरी पर हायर कर रही हैं. 12वीं के बाद यह कोर्स इंडस्ट्रियल रिचर्स लेबोरेटरी (कोलकाता) या यूनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से कर सकते हैं.

अन्य ऑफबीट कोर्स

फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून फॉरेस्ट से जुड़े कोर्स करवाता है.

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर से स्न्नश्चश्स्त्र ञ्जद्गष्द्धठ्ठश्चद्यशद्द4 में कोर्स कर सकते हैं.

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सायकाइट्री, रांची से थैरेपी, साइकोसर्जरी और ऑक्यूपेशनल कोर्स कर सकते हैं.

इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से कृषि में कोर्स कर सकते हैं.

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से प्लास्टिक टेक्नोलॉजी कोर्स करके लाखों कमा सकते हैं.

नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, नागपुर फायर इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं.

कस्टम विभाग में कैसे बन सकते हैं अधिकारी, ये रही योग्यता से लेकर चयन की पूरी जानकारी

हम सभी ने कस्टम विभाग का नाम कभी न कभी सुना ही होगा। कस्टम डिपार्टमेंट का काम देश में आयात और निर्यात होने वाले चीजों पर कर का निर्धारण और उसको वसूलने का काम करता है और साथ ही यह आयात और निर्यात हो रही चीजों की चेकिंग और तस्करी (स्मगलिंग) रोकने का होता है। इसीलिए इस विभाग में आप सरकारी नौकरी करने के साथ ही देश सेवा का मौका भी मिलता है और साथ ही समाज में प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है।

अगर आप भी कस्टम विभाग में अधिकारी बनना चाहते हैं तो इसलिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं और चयन प्रॉसेस को पूरा करना होता है। इसकी पूरी जानकारी आप यहां से हासिल करके इस दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं।

कौन बन सकता है कस्टम अधिकारी

कस्टम अधिकारी बनने के लिए उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाती है।

सिलेक्शन प्रॉसेस

कस्टम अधिकारी बनने के लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा को उत्तीर्ण करना होगा। इस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के बाद आप कस्टम डिपार्टमेंट में आईआरएस (सी एंड सीई) को प्राथमिकता देकर कस्टम अधिकारी बन सकते हैं।

यूपीएससी की ओर से यह परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसमें तीन चरण होते हैं। पहले चरण में प्रीलिम एग्जाम का आयोजन किया जाता है। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवार मेंस एग्जाम में भाग लेंगे और मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अंत में इंटरव्यू प्रॉसेस में शामिल होना होगा। सभी चरणों में किये गए प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है।

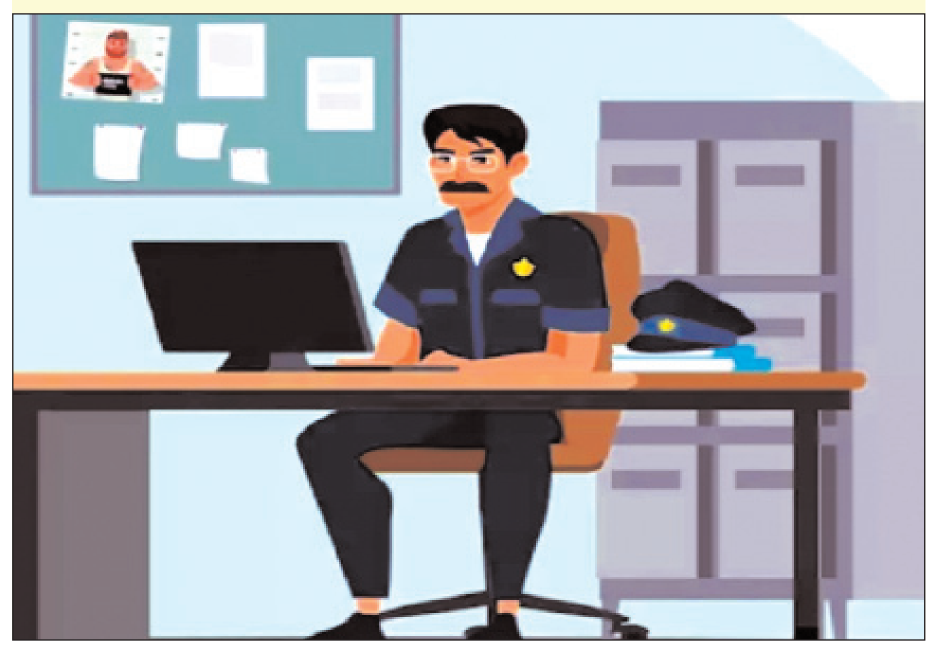

विदेश में मास्टर करने के लिए छात्र कैसे प्राप्त करें ऋण, ये रहे खास सुझाव

ऑस्ट्रेलिया में मास्टर डिग्री के लिए छात्र ऋण प्राप्त करना आपकी शिक्षा को वित्त पोषित करने में मदद कर सकता है। हमने प्रोडिजी फाइनेंस को इस विषय पर कुछ सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने परिचालन का विस्तार किया है और अब ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मास्टर करने के लिए छात्र कैसे ऋण प्राप्त करें, इसके लिए कुछ सुझाव और सलाह दी गई है-

अनुसंधान ऋण विकल्प- ऑस्ट्रेलिया में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उपलब्ध ऋण विकल्पों पर शोध करके शुरुआत करें। निजी ऋण दाताओं और सरकार समर्थित ऋण विकल्पों दोनों का अन्वेषण करें। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कुछ सामान्य ऋण विकल्पों में ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार, एंडेवर छात्रवृत्ति और निजी वित्तीय संस्थानों से ऋण शामिल हैं।

ऋण आवश्यकताओं को समझें- प्रत्येक ऋण विकल्प के लिए पात्रता मानदंड, ब्याज दरें, पुनर्भुगतान की शर्तें और ऋण सीमा की समीक्षा करें। क्रेडिट इतिहास, संपार्श्विक आवश्यकताओं, सहहस्ताक्षरकर्ता आवश्यकताओं और आवश्यक अतिरिक्त दस्तावेजीकरण जैसे कारकों पर ध्यान दें। प्रत्येक ऋण कार्यक्रम की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझें और निर्धारित करें कि क्या आप मानदंडों को पूरा करते हैं।

विश्वविद्यालयों और वित्तीय सहायता **कार्यालयों से संपर्क करें**- ऑस्ट्रेलिया में उन विश्वविद्यालयों में वित्तीय सहायता कार्यालयों या अंतर्राष्ट्रीय छात्र सेवाओं तक पहुंचें जहां आप अपने मास्टर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। अनुशंसित ऋण प्रदाताओं और किसी भी ऋण कार्यक्रम के बारे में पूछताछ करें जो वे सीधे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रदान करते हैं। वे उपलब्ध ऋण विकल्पों पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं।

दस्तावेज तैयार करें- ऋण आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इकट्ठा करें। इसमें विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, शैक्षणिक प्रतिलेख, वित्तीय क्षमता का प्रमाण, पहचान दस्तावेज और ऋण प्रदाता द्वारा आवश्यक कोई अन्य सहायक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सटीक हों, यदि आवश्यक हो तो अंग्रेजी में अनुवादित हों और आवश्यक प्रारूप में हों।

ऋण विकल्पों की तुलना करें- ब्याज दरों, पुनर्भुगतान शर्तों, ऋण सीमा और प्रस्तावित किसी भी अतिरिक्त लाभ या सुविधाओं के आधार पर आपके लिए उपलब्ध ऋण विकल्पों का मूल्यांकन करें। किसी भी अग्रिम शुल्क या शुल्क सहित ऋण की कुल लागत पर विचार करें। आपकी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त ऋण विकल्प खोजने के लिए विभिन्न उधारदाताओं की तुलना करें।

ऋण आवेदन जमा करें- सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज प्रदान करते हुए ऋण आवेदन पत्र सही-सही भरें। ऋणदाता द्वारा अनुरोध किए जाने पर अतिरिक्त दस्तावेज या जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार रहें। अपने आवेदन समय सीमा के भीतर जमा करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप सभी आवेदन समय सीमा को पूरा करते हैं।

बजट और पुनर्भुगतान योजना- एक बार जब आप छात्र ऋण सुरक्षित कर लेते हैं, तो अपने मास्टर प्रोग्राम के दौरान अपने खर्चों का प्रबंधन करने के लिए एक बजट बनाएं। अपनी ट्यूशन फीस, रहने की लागत, स्वास्थ्य बीमा और अन्य संबंधित खर्चों पर विचार करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने ऋण दायित्वों को पूरा कर सकें, एक पुनर्भुगतान योजना विकसित करें। ऋण पुनर्भुगतान की प्रभावी योजना बनाने के लिए संभावित रोजगार के अवसरों और अपेक्षित आय पर विचार करें।

पेशेवर मार्गदर्शन लें- यदि आपको कोई चिंता है या सहायता की आवश्यकता है, तो शिक्षा ऋण सलाहकारों या वित्तीय सहायता कार्यालयों से मार्गदर्शन लेने पर विचार करें। वे आपकी विशिष्ट स्थिति के आधार पर वैयक्तिकृत सलाह प्रदान कर सकते हैं और ऋण आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

किसी भी ऋण को स्वीकार करने से पहले हमेशा उसके नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें। ब्याज दरों, पुनर्भुगतान शेड्यूल और देर से या चूक गए भुगतान के लिए किसी भी दंड से सावधान रहें। जिम्मेदारीपूर्वक उधार लेना और ऑस्ट्रेलिया में अपने मास्टर प्रोग्राम के लिए आवश्यक ऋण राशि ही लेना महत्वपूर्ण है।

सैंपल पेपर सॉल्व करने के एक नहीं हैं तमाम फायदे, 10वीं, 12वीं के स्टूडेंट्स जरूर करें हल

सीबीएसई दसवीं और बारहवीं कक्षाओं के लिए अगले सप्ताह से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 15 फरवरी, 2024 से कंडक्ट होने वाले एग्जाम के लिए छात्र-छात्राओं ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। वहीं, जो थोड़ी- बहुत बची होंगी तो उन्हें वे निपटाने में जुटे होंगे। इसी क्रम में आज, हम आपको बताने जा रहे हैं कि बचे हुए वक्त में वे अपनी तैयारी को फाइनल रूप देने के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर की मदद ले सकते हैं।

हालांकि, अभी तक स्टूडेंट्स ने खुद भी कई Sample क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो ये प्रश्न पत्र आपकी बेहतर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें हल करने से न केवल आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी, बल्कि कई अन्य फायदे भी मिलते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

-पिछले पांच सालों के सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से न केवल परीक्षा की बेहतर प्रैक्टिस होती है, बल्कि घर पर ही एक एग्जाम जैसा माहौल क्रिएट करके निर्धारित समय-सीमा में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से टाइममैनेजमेंट भी सीख पाते हैं।

- निर्धारित समय-सीमा में प्रश्न पत्र हल कर लेने से स्टूडेंट्स के भीतर नर्वसनेस कम होती है। इसके साथ ही क्वेश्चन छूटने की गुंजाइश भी कम रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले से ही परीक्षा के पैटर्न और अन्य नियमों से परिचित रहते हैं और किस सेक्शन से कितने सवाल करना जरूरी है यह लगभग याद रहता है, इसलिए पेपर पूरा कर सकते हैं।

- सैंपल पेपर हल करने से याद करने के साथ-साथ आंसर लिखने की भी अच्छी प्रैक्टिस होती है, जो कहीं न कहीं आपको एग्जाम में बेहतर स्कोर करने में मदद करती है। इसके साथ ही, स्टूडेंट्स के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

तमिलनाडु में 15 पूर्व विधायक सहित कई भाजपा में शामिल

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले 15 पूर्व विधायकों और एक पूर्व सांसद सहित तमिलनाडु के कई नेता बुधवार को दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। इनमें से अधिकतर नेता राज्य में भाजपा की पूर्व सहयोगी अन्नाद्रमुक से हैं। के वडिवेल, एमवी रत्नम, आर चिन्नास्वामी और पीएस कंडासामी सहित पूर्व अन्नाद्रमुक नेता तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नेताओं का स्वागत करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि वे भाजपा में अनुभव का खजाना लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि वह लगातार तीसरी बार सत्ता में वापस आ रहे हैं। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ द्रमुक और उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक पर स्पष्ट रूप से निशाना साधते हुए कहा कि वे तमिलनाडु में हो रही घटनाओं को देख रहे हैं। राज्य भाजपा प्रमुख ने दावा किया, तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी की राह पर जा रहा है।

कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी का रेड

देहरादून। प्रवर्तन निदेशालय की टीम बुधवार को एक बार फिर से एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय को टीम उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मनी लांड्रिंग मामले में ये एक्शन लिया है। इस संबंध में टीम दिल्ली एनसीआर में भी एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली में कई ठिकानों पर ये रेड की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन की जांच के संबंध में ये कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर टीमें पहुंची हैं और तलाशी लेने में जुटी हुई है। बता दें कि हरक सिंह रावत वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के नेता है। वर्ष 2022 में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों से पहले ही उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया था।

दिल्ली में कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन

नईदिल्ली। कम कर हस्तांतरण और गैर-आनुपातिक संसाधन वितरण जैसे मुद्दों को लेकर बुधवार को केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर चलो दिल्ली विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। विरोध प्रदर्शन पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार हमारा विरोध सुनेगी और हमारा मुख्य इरादा राज्य और कन्नड़ लोगों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि जहां तक टैक्स कलेक्शन की बात है तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र नंबर एक पर है। दरअसल इस साल कर्नाटक टैक्स के रूप में 4.30 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान दे रहा है...अगर हम टैक्स के रूप में 100 रुपए इकट्ठा करते हैं और इसे भारत सरकार को देते हैं, तो हमें केवल 12-13 रुपए ही वापस मिल रहे हैं। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक इस देश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।

तलाशी लेने के बजाए पीए के घर में बैठे रहे ईडी के अधिकारी

नईदिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक (पीए) बिभव कुमार के आवास पर छापा मारने पहुंचे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी तलाशी लेने के बजाए उनके घर के 'लिविंग रूम' में बैठे रहे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बुधवार को यह दावा किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने किसी कमरे की तलाशी नहीं ली और न ही कोई दस्तावेज खंगाला। आतिशी ने संवाददाताओं से कहा कि अधिकारियों ने यह तक नहीं बताया कि वह किस मामले की जांच करने के लिए पहुंचे थे। आतिशी के दावों पर ईडी से कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड की निविदा प्रक्रिया में ''अनियमितताओं'' के संबंध में यह छापेमारी की गयी। आतिशी ने दावा किया कि पंचनामा दस्तावेज यह दर्शाता है कि ईडी की टीम कुमार के घर से दो जीमेल खातों के कुछ डाउनलोड और परिवार के तीन फोन अपने साथ ले गयी।

उत्तराखंड के यूसीसी बिल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी

हैदराबाद। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि प्रस्तावित कानून और कुछ नहीं बल्कि सभी समुदायों पर लागू होने वाला एक हिंदू कोड है। उन्होंने दावा किया कि विधेयक में हिंदुओं और आदिवासियों को छूट दी जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह संहिता मुसलमानों को एक अलग धर्म और संस्कृति का पालन करने के लिए मजबूर करती है, जो संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। एक्स पर ओवैसी ने लिखा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल और कुछ नहीं बल्कि सभी के लिए लागू एक हिंदू कोड है। सबसे पहले, हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? यदि आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं, तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है?

प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब

कांग्रेस ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र का गला घोंट दिया था : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर तंज कसे और कहा कि मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं उस दिन इन्हें बहुत ध्यान और आनंद से सुन रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में मनोरंजन की जो कमी हमें खल रही थी, वो इन्होंने पूरी कर दी थी। दरअसल प्रधानमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद में दिए भाषण का जिक्र कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में भारत की क्षमता, ताकत और उज्ज्वल भविष्य के बारे में बात की। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद देता हूं...।

इसके बाद कांग्रेस पर बरसते हुए कहा, हम बड़े धैर्य और नम्रता के साथ आपके एक-एक शब्द को सुनते रहे हैं। लेकिन आप आज भी न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। परंतु मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी है। इसलिए मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस 10 साल में 11वें नंबर पर देश को लेकर आ पाई। हम 10 साल में 5 नंबर लेकर आए। ये कांग्रेस हमें आर्थिक नीतियों पर भाषण सुना रही है। जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया। जिसने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, जिसने देश की सड़कों, गली-चौराहों पर अपने ही परिवार के नामों पर रख दिए, वो हमें सामाजिक न्याय पर भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं। वो मोदी की गांरटी पर सवाल उठा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी सोच से भी

आउटडेटेड हो गई है। जब सोच पुरानी हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दिनों तक राज करने वाला दल, ऐसी गिरावट। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं।

पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस ने सत्ता के लालच में लोकतंत्रा का गला घोंट दिया था। जिसने लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आई सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, जिस कांग्रेस ने देश की संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को जेल के सलाखों में बंद कर दिया था। जिसने अखबारों पर ताला लगाने की कोशिश की थी। जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नरेटिव गढ़ने का शौक पैदा हुआ था। अब उत्तर और दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र पर प्रवचन दे रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकेंगे। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है। इसलिए इस बार मैं भी पूरी तैयारी से आया हूं। मैंने सोचा था उस वक्त कि अगर आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं, तो मर्यादाओं का पालन करेंगे। लेकिन तब आपने क्या जुर्म किया था उस वक्त। उन्होंने कहा मैंने भी तब प्रार्थना की थी। की क्या थी मैं तो करता ही रहता हूं। पश्चिम बंगाल से एक आवाज आई थी कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं।

प्रधानमंत्री ने कहा मैंने सुना है लोकतंत्र में आपका कहने का अधिकार है और हमारी सुनने की जिम्मेदारी है। आज जो भी बातें हुई हैं, उसे मुझे देश के सामने रखना चाहिए। जब मैं सुनता हूं तब मेरा विश्वास पक्का हो गया कि यह पार्टी (कांग्रेस) सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। जब सोच आउटडेटेड हो गई है, तो उनका काम भी आउटडेटेड हो गया है। देखते ही देखते इतने दशकों तक देश पर राज करने वाला दल, इतना बड़ा दल, उसका यह हाल हो गया। हमें खुशी नहीं हो रही, हमें संवेदना है। लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, जब मरीज ऐसा हो तो।

जिस कांग्रेस की अपने नेता की कोई गारंटी नहीं, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कहते हैं हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। देश उनके 10 साल के कार्यकाल से क्यों नाराज था। इतना गुस्सा देश को क्यों आया। ये सब हमारे कहने से नहीं हुआ है। ये खुद के उनके कर्म हैं। जब लोगों ने उन्हें बहुत कुछ कहा हो तो मैं कुछ कहने की क्या जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कहा जाति के मामले पर कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की कांग्रेस जन्मजात विरोधी है, अगर बाबा साहेब आंबेडकर नहीं होते तो पता नहीं एससी, एसटी को आरक्षण भी मिलता या नहीं। मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को ज्यादा याद करता हूं। एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। उन्होंने लिखा था- मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं, जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। तभी मैं इन्हें जन्मजात विरोधी कहता हूं।

कांग्रेस ने लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण को निरर्थक बताया

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार को लोकसभा में दिये उनके भाषण की बेहद तीव्र निंदा करते हुए कहा कि वो अपने सबसे खराब स्थिति में हैं और उनका लोकसभा में दिया वक्तव्य बेहद निम्न दर्जे का था।

इसके साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि वैश्विक स्तर पर दिग्गज बौद्धिक नेता जवाहरलाल नेहरू को चुनिंदा रूप से उद्धृत करने के बजाय अपनी समझ को और गहरा करें। मीडिया के अनुसार कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी को पहले जवाहर लाल नेहरू के बारे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद उन्हें लेकर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। कांग्रेस ने भाजपा के लोकतंत्र, भ्रष्टाचार और विकास को लेकर अपनाये जा रहे दोहरेपन की ओर इशारा किया गया कि पीएम मोदी वंशवाद को लेकर केवल नेहरू-गांधी परिवार निशाना साधने की बजाय अपनी पार्टी में झांकने की कोशिश करें।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपना सबसे खराब भाषण दिया और निश्चित तौर पर वो राज्यसभा में भी ऐसा ही प्रदर्शन दोहराएंगे। वह गहरी असुरक्षाओं और जटिलताओं से ग्रस्त है, जिसके कारण वह नेहरू पर राजनीतिक रूप से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से शातिर तरीके से हमला करते हैं। अटल बिहारी वाजपेई और लालकृष्ण आडवानी ने कभी ऐसा नहीं किया लेकिन मोदी जी सोचते हैं कि वो चतुर हैं परन्तु वास्तव में वे जिस पद पर हैं, उसका अपमान करते हैं।

राज्यसभा सांसद रमेश ने आगे कहा, मेगालोमेनिया और नेहरूफोबिया एक जहरीला मिश्रण है, जो भारत में लोकतंत्र की हत्या का कारण बन रहा है। भारत के लोगों, विशेषकर युवाओं ने निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में नरेंद्र मोदी का आखिरी भाषण होगा।

जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के वंशवाद पर तंज कसते हुए उन्हें संघ परिवार में एक ऐसे परिवार को पेश करने की चुनौती दी, जिसने भारत की आजादी और राष्ट्र-निर्माण में योगदान दिया हो और नेहरू-गांधी परिवार जैसा सर्वोच्च बलिदान दिया हो। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, वे कौन सी विरासत लेकर चलते हैं? जब कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ रही थी और जेल की सजा काट रही थी, तब आरएसएस के लोग

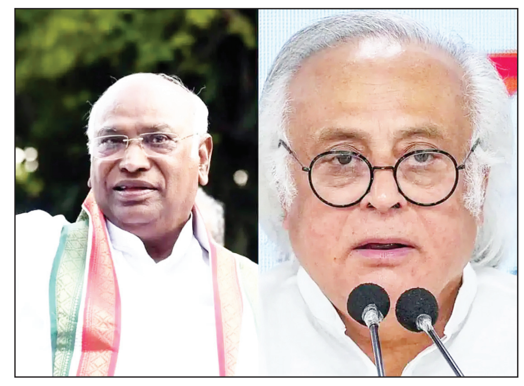

नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे थे। क्या आरएसएस-बीजेपी से किसी ने देश के लिए अपना जीवन बलिदान किया है? क्या 1989 में राजीव गांधी के हारने के बाद से गांधी परिवार से कोई प्रधानमंत्री बना है?

मोदी की इस टिप्पणी पर कि कांग्रेस सबसे बड़े ओबीसी को नहीं देखती, राहुल गांधी ने कहा-यह किसी व्यक्ति के ओबीसी होने के बारे में नहीं है। यह प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के बारे में है। जब हमने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया तो मोदी कहने लगे कि केवल दो जातियां हैं- अमीर और गरीब। अब वह कहते हैं कि वह सबसे बड़े ओबीसी हैं। जहां बड़े-छोटे को देखने की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, वहीं मोदी को पहले यह तय करना चाहिए कि जाति एक वास्तविकता है या नहीं। मोदी जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश रह रहे हैं क्योंकि वो जाति जनगणना के नाम से डरे हुए हैं?

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मोदीजी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के बारे में झूठ बोलना बंद करें। यदि गरीबी कम हुई है तो उपभोग वृद्धि केवल 4.4 प्रतिशत क्यों है? आपकी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए क्यों मजबूर है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत क्यों गिर रहा है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के संकेतक साबुन, तेल, शैम्पू, बिस्कुट जैसी वस्तुएं अधिक क्यों नहीं बिक रही हैं? आपके शासनकाल में क्रय शक्ति पर आधारित प्रति व्यक्ति आय वृद्धि मात्र 4.3 प्रतिशत है, जो मनमोहन सिंह के शासनकाल में 6.2 प्रतिशत थी।

खेल
प्रमुख समाचार

टेस्ट क्रिकेट में बरकरार है फैब फोर का जलवा

नई दिल्ली। टेस्ट क्रिकेट में फैब फोर का जलवा बरकरार है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये फैब फोर क्या है तो बता दें कि ये तमगा मौजूदा दौर में क्रिकेट में सक्रिय दुनिया के चार सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को दिया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, इंग्लैंड के जो रूट, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और भारत के विराट कोहली शामिल हैं।

फैब फोर का जिक्र इस कारण हो रहा है क्योंकि वर्तमान में क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ियों में टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में यही चार खिलाड़ी एक के बाद टॉप फोर में हैं। इसके बाद पांचवें नंबर का खिलाड़ी इनसे बहुत दूर है। फैब फोर में शामिल ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ 32 शतक के साथ मौजूदा दौर में क्रिकेट में सक्रिय खिलाड़ियों में टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन हैं जिनके नाम 31 शतक दर्ज हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद इंग्लैंड के जो रूट ने 30 शतक लगाए हैं और भारतीय स्टार विराट कोहली 29 शतकों के साथ चौथे नंबर पर हैं। मौजूदा दौर में क्रिकेट में सक्रिय खिलाड़ियों में टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में पांचवें नंबर पर भारत के चेतेश्वर पुजारा हैं जिन्होंने 19 शतक लगाए हैं। श्रीलंका के दिमुथ करुणारत्ने छठे नंबर हैं जिन्होंने 16 शतक जड़े हैं। सातवें नंबर पर मौजूद श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज के नाम भी 16 शतक दर्ज हैं। आठवें नंबर पर 15 शतकों के साथ ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा हैं। इसके बाद श्रीलंका के दिनेश चांदीमल का नंबर आता है जिन्होंने भी 15 शतक लगाए हैं। बता दें कि इस मुकाम पर न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के एक ही मैच की दोनों पारियों में शतक लगाकर पहुंचे। मैच में पहली पारी में शतक जड़ने वाले अनुभवी केन विलियमसन ने दूसरी पारी में भी शतक लगाया। टेस्ट में यह उनका 31वां शतक था।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी ने दर्ज की बढ़त

नईदिल्ली। बुधवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ ओपन हुए लेकिन, आईटी और फाइनैंशियल सेक्टर्स के शेयरों में जारी मुनाफावसूली के चलते इंट्रा डे में मामूली फिसलन देखने को मिली। जिसका असर आज बीएसई पर देखने को मिला। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 24.13 अंक या 0.03 फीसदी की गिरावट के साथ 72,210.22 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 हरे निशान पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 आज 1.10 अंक की वृद्धि के साथ 0.01 फीसदी की बढ़त दर्ज करते हुए 21,930.50 पर बंद हुआ। एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, ऐक्सिस बैंक, बजाज फाइनैंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया, एशियन पेंट्स, सन फार्मा, रिलायंस, टाइटन और मारुति इंडिया आज चढ़कर बंद हुए।

एथर इंडस्ट्रीज भरूच में सोलर पॉवर प्लांट चालू करेगी

नईदिल्ली। एथर इंडस्ट्रीज अधिक टिकाऊ बनने के मकसद से गुजरात के भरूच में निजी इस्तेमाल के लिए 15 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना चालू करेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा है कि यह परियोजना गुजरात के भरूच जिले में 60 एकड़ में स्थापित की जाएगी। सौर ऊर्जा संयंत्र की चरणबद्ध शुरुआत अगले वित्त वर्ष के आरंभ में होने की संभावना है। हालांकि कंपनी ने इस परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय का ब्योरा नहीं दिया है। एथर इंडस्ट्रीज इसके पहले जुलाई, 2023 में भी निजी उपभोग के लिए 16 मेगावाट की एक सौर ऊर्जा परियोजना चालू कर चुकी है। कंपनी ने कहा कि भरूच में लगने वाली नई सौर परियोजना उसके नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों में वृद्धि करेगी और उसे टिकाऊ स्थिति की तरफ ले जाने में मदद करेगी।

लार्सन एंड टुब्रो को भारत, प. एशिया में मिले कई बड़े ऑर्डर

नईदिल्ली। लार्सन एंड टुब्रो ने बुधवार को कहा कि उसके बिजली पारेषण और वितरण व्यवसाय को घरेलू बाजार एवं पश्चिम एशिया में कुछ बड़े ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने बीएसई को इसकी सूचना दी। कंपनी के वर्गीकरण के तहत 2,500 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये तक के ऑर्डर बड़े ऑर्डर की श्रेणी में आते हैं। कंपनी को एक बांध पर 75 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक इकाई लगाने का ऑर्डर मिला है। यह संयंत्र अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क का हिस्सा है जिसे झारखंड और पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी निगम के जलाशय पर विकसित किया जा रहा है। एलएंडटी ने कहा, सऊदी अरब में कंपनी को एक बिजली सब-स्टेशन के निर्माण का ऑर्डर मिला है। कुवैत और सऊदी अरब में हाइड्रोकार्बन कंपनियों से कंपनी को सब-स्टेशन और वोल्टेज रूपांतरण के भी ऑर्डर मिले हैं। यूएई में चल रहे 220 किलोवोल्ट बिजली आपूर्ति परियोजना में भी अतिरिक्त ऑर्डर मिला है।

टाटा स्टील सहयोगी टीआरएफ लिमिटेड का नहीं करेगी मर्जर

नईदिल्ली। टाटा स्टील ने बुधवार को कहा कि उसके बोर्ड ने सहयोगी कंपनी टीआरएफ लिमिटेड का मर्जर नहीं करने का फैसला किया है। यह फैसला सहयोगी कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन में आ रहे सुधार को देखते हुए लिया गया है। टाटा स्टील ने पहले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ, द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड, एस एंड टी माइनिंग कंपनी सहित अपने नौ रणनीतिक व्यवसायों के एकीकरण की घोषणा की थी। टाटा स्टील ने एक बयान में कहा, दोनों कंपनियों के बोर्ड ने विलय प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। टाटा स्टील के सक्रिय समर्थन से, टीआरएफ ने बेहद चुनौतीपूर्ण परिचालन माहौल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जिससे उसके व्यावसायिक प्रदर्शन में बदलाव आया है।

कामयाबी की सीढ़ी बनी टीम इंडिया की नयी पीढ़ी

अनुराग भारती

नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी...ये है टीम हिंदुस्तानी। क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट में टीम इंडिया का नया जोश रंग दिख रहा है। टीम की यूथ ब्रिगेड मैदान पर बदलाव की नई कहानी लिख रही है।

हैदराबाद में जब इंग्लिश टीम के बैजबॉल और स्पिन बॉल के सामने मेजबान जब औंधे मुंह गिरे तो सवाल कई उठे। खराब फॉर्म की वजह से बाहर किए अनुभवी टेस्ट बल्लेबाजों को वापस बुलाने की मांग भी उठने लगी। हालांकि यूथ ब्रिगेड ने इसका जवाब वाइजेग में बल्ले से मैदान पर विजय की कहानी लिखकर दिया। उसने इशारा कर दिया है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या फिर रेड बॉल फॉर्मेट, अपने हुनर से हार को जीत में बदलना उन्हें आता है।

सबसे पहले बात उस चेहरे की जिसकी चमक देखकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया। अगर कोई बल्लेबाज 22 साल की उम्र पूरा करते करते मैदान पर दोहरा शतक जड़ने की कहानी लिख दे तो ऐसा होना लाजमी है। यशस्वी जायसवाल ने साबित कर दिया कि जिंदगी की जंग हो या फिर क्रिकेट का मैदान, उन्होंने ठान लिया है कि हार नहीं मानूंगा।

क्रिकेट गेंद का रंग चाहे सफेद हो या फिर रंगीन, रनों की भूख और खेल के लिए यशस्वी का जुनून नहीं बदलता। विरोधियों पर छा जाने के उनके आक्रामक अंदाज को इसी बात से समझिए उन्होंने अपना शतक छक्के के साथ और दोहरा शतक चौका जड़कर पूरा किया। यही बात उन्हें दूसरे बल्लेबाजों से अलग बनाती है। इसीलिए तो ये भी कहा जा रहा है कि मैदान पर बैजबॉल नहीं जैशबॉल का जलवा दिख रहा है।

यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाज़ी का लोहा बड़े-बड़े दिग्गज इसलिए मान रहे हैं क्योंकि उनकी 209 रन की पारी टर्न और बाउंस भरे विकेट और ऐसे वक्त पर आई जब दूसरे छोर से बड़े-बड़े बल्लेबाजों के आने और जाने का सिलसिला जारी था।

कभी डेयरी में काम करने और गोल गप्पे बेचने के दौर से गुजर चुके यशस्वी मिले मौके को भुनाने का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। उनकी इसी काबिलियत ने उन्हें सचिन, कांबली और शास्त्री के साथ उस एलीट क्लब में शामिल करा दिया जिन्होंने अपने 23वें बर्थडे से पहले घरेलू मैदान और विदेशी जमीन, दोनों ही जगहों पर शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है।

आत्मविश्वास से भरे यशस्वी जायसवाल के तरकश में हर वो तीर मौजूद है जो विरोधी गेंदबाज़ों को परेशान कर सकता है और उनकी लाइन-लेंग्थ को बिगाड़ सकता है। वाइजेग टेस्ट की पहली पारी में उनकी बल्लेबाज़ी इसकी बानगी है। यशस्वी ने न सिर्फ बड़े आराम से जमीनी शॉट खेले, बल्कि हवाई शॉट खेलने में भी उनकी सहजता देखते ही बनी। पारी में खेले उनके कट शॉट, ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट बताते हैं कि उनकी तकनीक कितनी मजबूत है। यशस्वी ने अपनी बल्लेबाजी से ये अहसास करा दिया है कि वो तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए पारी शुरू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि यशस्वी खुद ये बात कहते हैं कि हर फॉर्मेट अलग होता है, गेंद अलग होती है, मैदान अलग होता है, इसलिए वे अलग माइंडसेट के साथ खेलने उतरते हैं। वहीं उनके सलामी जोड़ीदार कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि यशस्वी खेल को अच्छी तरह समझते हैं और वे टीम के लिए बेहतरीन योगदान दे सकते हैं लेकिन उन्हें अभी लंबा सफर तय करना है, ऐसे में जरूरत है कि वे विनम्र रहें यानी उनके पैर जमीन पर रहें। एक और युवा बल्लेबाज ने अपनी बल्लेबाज़ी से फिर अहसास करा दिया कि फॉर्म इज टेंपरेरी बट क्लास इज परमानेंट। नाम है शुभमन गिल। 2023 में क्रिकेट के हर फॉर्मेट में गिल का बल्ला रन उगलता दिखा था। हालांकि 2024 में टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने पारी की शुरूआत करने के बजाय तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की गुजारिश की। टीम मैनेजमेंट ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन पर भरोसा भी जताया लेकिन पहली तीन पारियों में मिली नाकामी के बाद उन पर उंगलियां भी उठने लगी। तीन में से दो पारियों में वो अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए।

तीसरे दिन भी महतारियों ने दिखाया जबरदस्त उत्साह

अबतक 16 लाख 81 हजार से ज्यादा महिलाओं ने भरा आवेदन

रायपुर। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरंभ की गई महतारी वंदन योजना के लाभ के लिए तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में आवेदन भरने का सिलसिला जारी रहा. इस योजना के तहत तीन दिनों में ही प्रदेश में 16 लाख 81 हजार 968 आवेदन प्राप्त हुए हैं. आज आवेदन भरने के तीसरे दिन 8 लाख 73 हजार 391 महिलाओं ने कैंपों में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है. इस योजना के लाभ को लेकर महिलाओं में बेहद उत्साह है. महिलाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर महीने मिलने वाली एक हजार रूपए की राशि से वह अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी और सम्मानजनक जीवन निर्वाह कर सकेंगी

आवेदन जमा किया. अब तक सर्वाधिक एक लाख 38 हजार 994 आवेदन महासमुंद जिले में भरे गए हैं. महतारी वंदन योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले में एक लाख 23 हजार 546 तथा रायपुर जिले में एक लाख एक हजार 461 आवेदन प्राप्त हुए हैं. महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं से सहजता से आवेदन प्राप्त करने एवं उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देने के लिए सभी जिलों में कलेक्टरों के निर्देशन में बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रक्रिया में अधिक समय न लगे इसके लिए प्रशासन ने पात्रता संबंधी नियमों को बताने और जरूरी दस्तावेज चेक करने के लिए कर्मचारी तैनात किए हैं

प्रदेश में हर तरफ महतारी वंदन का माहौल है. आवेदन भरने को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है. सभी जिलों में लग रहे

जिलावार प्राप्त आवेदन

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक बालोद में 56 हजार 983, बलौदाबाजार में 31 हजार 529, बलरामपुर में 40 हजार 328, बस्तर में 68 हजार 621, बेमेतरा में 78 हजार 81 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। इस प्रकार बीजापुर में 4 हजार 153, बिलासपुर में 73 हजार 924, दंतेवाड़ा में 24 हजार 973, धमतरी में 39 हजार 54, गरियाबंद में 50 हजार 795, जांजगीर में 98 हजार 849, जशपुर में 59 हजार 197, कांकेर में 27 हजार 401, कवर्धा में 57 हजार 151, कोंडागांव में 54 हजार, कोरबा में 47 हजार 140, कोरिया में 18 हजार 724, मुंगेली में 42 हजार 953, नारायणपुर में 3250, रायगढ़ में 52 हजार 327, राजनांदगांव में 60 हजार 614, सरगुजा में 38 हजार 600, सुकमा में 10 हजार 74, सूरजपुर में 80 हजार 119, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 43 हजार 925, सक्ती में 37 हजार 506, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 27 हजार 295, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में 8295, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 11 हजार 295, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 71 हजार 550 आवेदन आज तक प्राप्त हो चुके हैं.

राज्यपाल हरिचंदन ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी

राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर उन्हें भारत रत्न सम्मान मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने उन्हें पुष्पगुच्छ और रामलला की प्रतिमा स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की।

छत्तीसगढ़ी संस्कृति से विदेशी छात्रों का प्रभावित होना गौरव का क्षण - अग्रवाल

रायपुर। शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से साउथ कोरियन छात्रों के प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान पर्यावरण, मानवाधिकार और जन कल्याण जैसे मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। श्री अग्रवाल ने कहा कि विदेशी छात्रों का छत्तीसगढ़ी संस्कृति से प्रभावित होना हमारे लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। एएसईजेड साउथ कोरिया छात्रों से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में पर्यावरण संबंधित समस्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। शिक्षण संस्थानों में पर्यावरण जागरूकता पर जोर देकर हम छात्रों को पर्यावरण के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। इन संस्थानों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। पर्यावरण के अनुकूल बुनियादी ढांचे जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि एएसईजेड विश्वविद्यालय के छात्र स्वयंसेवकों का एक वैश्विक संगठन है। जो दुनियाभर में सेव द अर्थ मुहिम चलाती है। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर जनजागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

मेरी बात ✍ गिरीश पंकज

कब मिलेगी गद्दारों से मुक्ति?

बहुत पहले एक फिल्मी गीत सुना था, ''संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से।'' महान गीतकार प्रदीप ने सन 1958 में आई फिल्म 'तलाक' के लिए यह लिखा था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं,

बिगुल बाज रहा आज़ादी का गगन गूँजता नारों से,
मिला रही है आज हिंद की मीठी नज़र सितारों से।
एक बात कहनी है लेकिन आज देश के प्यारों से,
जान से नेताओं से फ़ौजों की खड़ी कतारों से,
कहनी है हम इक बात देश के पहरेदारों से,
संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से,
झाँक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से।
संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से।

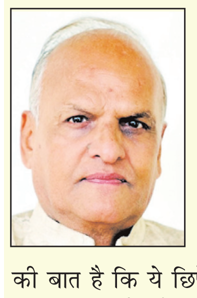

आजादी के ग्यारह साल बाद का यह गीत कवि प्रदीप ने लिखा था,तब निस्संदेह उनके सामने कुछ गद्दार चेहरे भी रहे होंगे, वरना वे ऐसी रचना करते ही क्यों ? उन्होंने देशप्रेम की अनेक महान रचनाएं लिखी हैं। जैसे 'ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी', तो काफी लोकप्रिय हुआ लेकिन उन्होंने गद्दारों के बारे में भी लिखा कि उनसे संभाल कर रहना है। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय कुछ गद्दार सक्रिय थे। दुर्भाग्य की बात है कि ये छिपे हुए गद्दार दिनोंदिन बढ़ते ही चले गए । इतने अधिक बढ़ गए कि ये लोग दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे तक लगाने लगे, 'भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह!' जो देश के टुकड़े करने की बात करता हो, तो इससे बड़ा गद्दार कोई और हो नहीं सकता।

अभी कुछ दिन पहले दक्षिण भारत के एक नेता ने देश विरोधी बयान दिया कि दक्षिण भारत के राज्यों को अपना देश बनाने की मांग करनी चाहिए। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी अपने लोगों को भड़काने वाले भाषण निरंतर देते रहते हैं। समाज में समरसता को खत्म करने वाले भाषण भी देश के साथ गद्दारी है । पिछले दिनों मेरठ से एक व्यक्ति पकड़ा गया जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा थाम इसके पहले भी अनेक जासूस पकड़े जाते रहे हैं। इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। इन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। भले ही देश को नुकसान पहुंचे। विचारधारा के स्तर पर भी अनेक तथाकथित प्रगतिशील लेखक, फर्ज़ी समाजसेवी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। जेएनयू में जो भारत विरोधी नारे लगे तो उसे अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा माना गया। अफ़ज़ल गुरु जैसे खतरनाक आतंकवादी को फांसी दी गई, तो जेएनयू में यह नारा भी लगा कि 'अफजल हम शर्मिंदा हैं,तेरे कातिल जिंदा हैं'। जिस देश में इस तरह की पीढ़ी सक्रिय हो, उस देश की आंतरिक सुरक्षा पर हर समय खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए भारत सरकार का दायित्व है कि ऐसे तमाम लोगों पर फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, जो देश विरोधी बातें करते हैं । पिछले दिनों बेंगलुरु के कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने यहां तक कह दिया कि दक्षिणी राज्यों को एक अलग राष्ट्र मांग के लिए आवाज उठानी चाहिए। हालांकि वह केंद्र द्वारा पर्याप्त धनराशि न दिए जाने के विरोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ऐसा कह रहे थे, लेकिन ऐसा विचार आना ही अपने आप में खतरनाक है। केंद्र द्वारा राज्यों को मिलने वाले अनुदान कम-ज्यादा होते रहते हैं। इसे लेकर अलग राष्ट्र की मांग उठाना ही अपने आप में सांसद की गंदी मानसिकता को दर्शाता है। बहुत पहले उत्तर प्रदेश के सपा नेता आज़म खान ने भारत माता को डायन कह दिया था। राष्ट्रगान का अपमान, तिरंगे का अनादर तो आए दिन होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि धीरे-धीरे कुछ लोगों के मन में देशप्रेम शून्य होता जा रहा है। यह चिंता की बात है । अलग देश पर की मांग करने वाले संसद पर तो कायदे उसे फौरन देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन हमारे यहां कई बार इतनी अधिक उदारता बरती जाती है कि लोगों के हौसले बुलंद होते रहते हैं, और वे देशविरोधी बातें करने को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा मान लेते हैं । हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, 'जिस थाली में खाया उसी में छेद किया'। देश के कुछ लोग यही कर रहे हैं । भारत देश में रह रहे हैं, इसका अन्न-जल खा-पी कर मोटे ताजे हो रहे हैं, इस देश को अनेक सुविधाएं लेकर शान से जी रहे हैं मगर वक्त पड़ने पर इसी देश को गाली भी दे रहे हैं। यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे अराजक तत्वों को फौरन गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इस तरह की हिम्मत न कर सकें।

इसरो और मद्रास आईआईटी के अध्ययन भ्रमण से लौटे जशपुर के मेधावी विद्यार्थियों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही

अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को भेजा गया था अध्ययन भ्रमण पर

रायपुर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन की एक्सपोजर विजिट से लौटे जशपुर के मेधावी बच्चों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही देखी। इन बच्चों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से भी मुलाकात की। देश के ख्यातिलब्ध उत्कृष्ट तकनीकी संस्थानों का भ्रमण करने के बाद बच्चे काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश पर आदिवासी बहुल जशपुर जिले के बच्चों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान तथा अनुसंधान के अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसरो और आईआईटी मद्रास के भ्रमण पर भेजा गया था। बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अध्ययन भ्रमण के

दौरान उन्होंने वैज्ञानिकों और आईआईटी के छात्रों से मुलाकात की और कहा कि हम भी उन्ही की तरह परीक्षा उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर अपने जिले और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।

अध्ययन भ्रमण से लौटने के बाद जशपुर जिले के 43 मेधावी छात्र-छात्राओं ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण कर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से विधानसभा में मुलाकात की। जशपुर जिले के ये छात्र-छात्राएं स्वामी आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल पत्थलगांव, बगीचा और जशपुर, संकल्प शिक्षण संस्थान कुनकुरी और जशपुर तथा उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला बगीचा के कक्षा 11वीं के छात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक भ्रमण करके आप लोग आज यहां विधानसभा का भ्रमण करने आये हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।

मुख्यमंत्री ने बच्चों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के बारे में जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखी गई किताब ''एग्जाम वारियर्स'' के बारे में पूछा। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने घोषणा की कि अगले शैक्षणिक सत्र से 9वीं से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को ''एग्जाम वारियर्स'' किताब का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि वे लगन और मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी में जुटें और अपने परिवार, स्कूल और प्रदेश का नाम रोशन करें। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जशपुर जिले के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की एक अच्छी पहल है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

2 लाख 34 हजार किसान नहीं बेच पाए हैं अपना धान

रायपुर। विष्णुदेव सरकार पर किसान विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जैसे ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, धान खरीदी को बाधित करने प्रशासनिक दबाव बनाकर तरह-तरह के व्यवधान उत्पन्न किये गए। षड्यंत्र पूर्वक टोकन जारी करने और तौलाई की गति को धीमी कर दिया गया, बरदानों के लिए किसान भटकते रहे, मौसम का बहाना कर अनेकों धान संग्रहण केंद्रों में कई-कई दिनों तक तौलाई बंद रखा गया। तहसीलदार, पटवारी और समिति प्रबंधकों पर दबाव डालकर जबरिया रकबा समर्पण करवा कर किसानों को धान बेचने से वंचित किया गया। वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2023-24 के लिए समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए कुल 26 लाख 63 हजार किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है, लेकिन खरीदी मात्र 23 लाख 29 हजार किसानों से की गई, अर्थात 2 लाख 34 हजार किसान अपना धान नहीं बेच पाए। कुल पंजीकृत रकबा 32 लाख 99 हजार हेक्टेयर में से लगभग 27 लाख 91 हजार हेक्टेयर रकबे का ही धान अंतिम तिथि तक खरीदा गया, अर्थात् लगभग 6 लाख हेक्टेयर का धान अब तक उपार्जन से वंचित है।

विधानसभा में उठा स्काई वाक का मुद्दा

रायपुर। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने विधानसभा में आज स्काई वाक पर सवाल उठाया,उन्होने रायपुर शहर में स्काई वाक निर्माण की अद्यतन स्थिति व स्काई वाक के संबंध में ईओडब्ल्यू में की गई शिकायत की स्थिति पर जानकारी चाही। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरूण साव की तरफ से दिया गया लिखित जवाब में बताया गया कि स्काई वाक का निर्माण 5 अप्रैल 2019 से बंद है। 01 मार्च 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के बाद की गई समीक्षा बैठक के बाद निर्माण कार्य रोका गया। शासन की सामान्य सुझाव समिति ने दिया था शास्त्री चौक पर निर्माणाधीन स्काई वाक फुट ओवर ब्रिज का शेष कार्य पूरा करने का सुझाव। ईओडब्ल्यू ने इस विषय पर विधानसभा में अपने लिखित उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि स्काईवाक के निर्माण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गई है तथा प्रकरण इस प्रकरण को फाइल क्लोज कर दिया है।

भगत के 13 करीबियों की प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी

रायपुर। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, और उनके करीबियों पर आयकर का शिकंजा कसता रहा है। अब नयी जानकारी ये है कि आयकर विभाग ने सरगुजा कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर अमरजीत भगत के 13 करीबियों की प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी है। भगत और उनके करीबियों के यहां आयकर की जांच पूरी हो गई है और अब बेनामी संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। अंबिकापुर में भगत के करीबी टिम्बर व्यापारी राजू अग्रवाल के यहां भी आयकर ने दबिश दी थी। छापेमारी के बाद राजू गायब है, लेकिन उनके घर के तीन कमरों को सील कर पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। इन सबके बीच आयकर विभाग ने अंबिकापुर कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। विभाग ने 13 लोगों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। विभाग ने पिछले पांच साल में जमीन की खरीदी और बिक्री की जानकारी मांगी है। साथ ही रियल इस्टेट कारोबार में निवेश अथवा अन्य प्रॉपर्टी के साथ-साथ जमीन आबंटन के अलावा एफआरए व अन्य बेनीफिट का डिटेल उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इन 13 लोगों के यहां पिछले दिनों आयकर टीम ने जांच-पड़ताल भी की थी। जिन लोगों का ब्यौरा मांगा गया है, उनमें मैनपाट के मनोज यादव, अतुल यादव, गणेश यादव, नागेश्वर यादव, अंबिकापुर के सुरेश यादव, गंगापुर खुर्द के प्रमोद टोप्पो, अंबिकापुर के राजू अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, बतौली के हेमंत यादव, रामानंद यादव, दीना यादव, और प्रदीप गुप्ता हैं।

जलजीवन मिशन के अपूर्ण कार्य जल्द होंगे पूरेः साव

रायपुर। बुधवार को विधानसभा में जलजीवन मिशन के अपूर्ण कार्यों को लेकर मामला उठा। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सवालों का जवाब देते हुए काम जल्द से जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में भाजपा के धरमजीत सिंह ने तखतपुर विधानसभा में अपूर्ण कार्यों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान पूर्व विधायक ने तखतपुर में पानी की गंगा बहाने का दावा किया था। लेकिन इतना पानी बहा कि सेना बुलानी पड़ी, और आज मंत्रीजी बता रहे हैं कि काम अधूरे हैं। जिन्हें 30 मार्च 24 तक पूरा करने का आश्वासन दिया है। यह बताए, कब तक पूरा करेंगे। मंत्री साव ने कहा कि अलग-अलग कारणों से कार्य प्रगति नहीं हो पायी। पिछली सरकार के समय जेजेएम ने राज्य 35 नंबर पर थी और अब 24 नंबरों पर है। हमने तेजी से काम किया है। केवल 9 कार्य पूर्ण है। शेष तेजी से पूर्ण कर लेंगे। धरमजीत सिंह ने कहा यह सिर्फ तखतपुर की समस्या नहीं है पूरे प्रदेश की समस्या है। किसी भी विधायक के क्षेत्र में काम पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदारों ने जमीन विवाद कहकर काम छोड़ दिया है और पैसे ले लिए हैं। मंत्री साव ने कहा काम छोड़ने की बात सही है। हम तेजी से पूरा करवाएंगे। कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि काम में देरी पर पेनाल्टी से बचने के लिए ठेकेदार टंकी निर्माण हेतु जमीन विवाद कहकर छोड़ दे रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री शर्मा की पहल पर मस्कट में बंधक महिला मुक्त

रायपुर। परित्राणाय साधुनाम, गीता के इस वाक्य को छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना ध्येय वाक्य रखा है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर विदेशों में भी फंसे लोगों की मदद के लिए पहल कर इस वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं। मस्कट में बंधक बनाई गई खुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका के मामले में ओमान स्थित इंडियन एम्बैसी से उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लगातार संपर्क किया। त्वरित की गई कार्रवाई के पश्चात दीपिका को सुरक्षित एम्बैसी लाया गया। ओमान में इंडियन एम्बेसडर से उपमुख्यमंत्री लगातार संपर्क में रहे। विधानसभा से भी वे लगातार इस मामले पर अपडेट लेते रहे। उन्होंने बंधक बनाई गई महिला से बातचीत भी की। उन्होंने दीपिका से सबसे पहले हालचाल पूछा। दीपिका ने बताया कि अभी बिल्कुल सुरक्षित हूँ। मस्कट की एम्बैसी में आ गई हूँ। श्री शर्मा ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिये। आपके आने की व्यवस्था हम करेंगे। आप मेरा नंबर रख लीजिए। आप छत्तीसगढ़ आने के बाद मुझे फोन करिये और आप अपने साथ मस्कट में हुए वाकये के बारे में बताइये। आपको जिन लोगों ने धोखा दिया, उस मामले की तह में जाकर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले की निवासी जे. मुकेश ने पुलिस को आवेदन दिया कि उनकी पत्नी खुर्सीपार निवासी जोगी दीपिका नामक महिला को घरेलू काम दिलाने के बहाने हैदराबाद निवासी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति ने ओमान देश की राजधानी मस्कट निवासी हाफिजा के घर गत वर्ष मई 2023 में भेजा था।

खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने विजेता टीम को किया पुरस्कृत

एयर फोर्स ने जीती महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता

रायपुर। खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने आज राजनांदगांव जिले में आयोजित महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 के विजेता टीम को पुरस्कृत किया। 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का फायनल मैच एकतरफा रहा, जिसमें इंडियन एयर फोर्स नई दिल्ली ने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली को 5-1 गोल से हराकर प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा कर लिया। तीसरे व चौथे स्थान के लिए खेला गया मैच भी एकतरफा रहा। जिसमें आर्मी स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड नई दिल्ली ने सेल हॉकी अकादमी राउरकेला को 7-2 गोल से हराकर तीसरे स्थान पर रही। दिग्विजय स्टेडियम समिति द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेली गई, 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के फायनल मैच में एयर फोर्स नई दिल्ली ने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली को 1 गोल के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त देकर प्रतियोगिता के खिताब पर कब्जा किया। इसके पूर्व तीसरे व चौथे स्थान के लिए खेले गए मैच में आर्मी इलेवन ने सेल राउरकेला को आसानी से 7-2 गोल से हराकर तीसरा स्थान

किया और सेल की टीम चौथे स्थान पर रही। प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण करते हुए खेल मंत्री श्री टंकराम वर्मा एवं अन्य अतिथियों ने विजेता टीम को आयोजन समिति द्वारा विशाल चांदी की ट्रॉफी एवं छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री बल्देव सिंह भाटिया द्वारा प्रदत्त 5 लाख रूपए, आयोजन समिति द्वारा उपविजेता टीम को विशाल चांदी की ट्रॉफी एवं समाजसेवी बहादुर अली द्वारा प्रदत्त 3 लाख रूपए, तृतीय स्थान प्राप्त टीम आर्मी इलेवन सी.एन. तिवारी ट्रॉफी एवं श्री रमेश नरेश डाकलिया द्वारा प्रदत्त 51 हजार रूपए और चौथा पुरस्कार सेल अकादमी को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री मृणाल चौबे द्वारा प्रदत्त ट्रॉफी एवं 21 हजार रूपए प्रदान किया गए।

एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट रायपुर को जटिल हृदय रोग के इलाज में मिली बड़ी सफलता

रायपुर। पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट (एसीआई) में कॉर्डियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. स्मित श्रीवास्तव एवं टीम ने ट्रांसकैथेटर माइट्रल वाल्व इम्प्लांट (टीएमवीआर) वॉल्व इन वॉल्व प्रक्रिया के जरिए एक 70 वर्षीय महिला मरीज की जिंदगी बचाई। इस प्रक्रिया के साथ एसीआई पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में मरीज की छाती पर बिना किसी चीरे के माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट प्रक्रिया को पूरा करने वाला पहला और एकमात्र संस्थान बन गया। डॉ. स्मित श्रीवास्तव के अनुसार

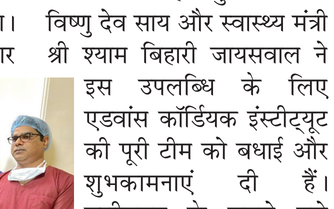

माइट्रल वाल्व को रोगी की जांघ की नसों के माध्यम से एंजियोप्लास्टी में हृदय की नसों में स्टेंट लगाने के समान प्रक्रिया द्वारा प्रत्यारोपित किया गया। मरीज़ को 26 एम. एम. का माइट्रल वॉल्व लगाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि के लिए एडवांस कॉर्डियक इंस्टीट्यूट की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल, डॉ. भीम राव अंबेडकर अस्पताल से संबद्ध एडवांस कॉर्डियक इंस्टीट्यूट जटिल हृदय रोग के सफल इलाज में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहा है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.